

ओऽम्

वैदिक संस्कृति का उद्घोषक

वैदिक सार्वदेशिक

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली का साप्ताहिक मुख्य-पत्र

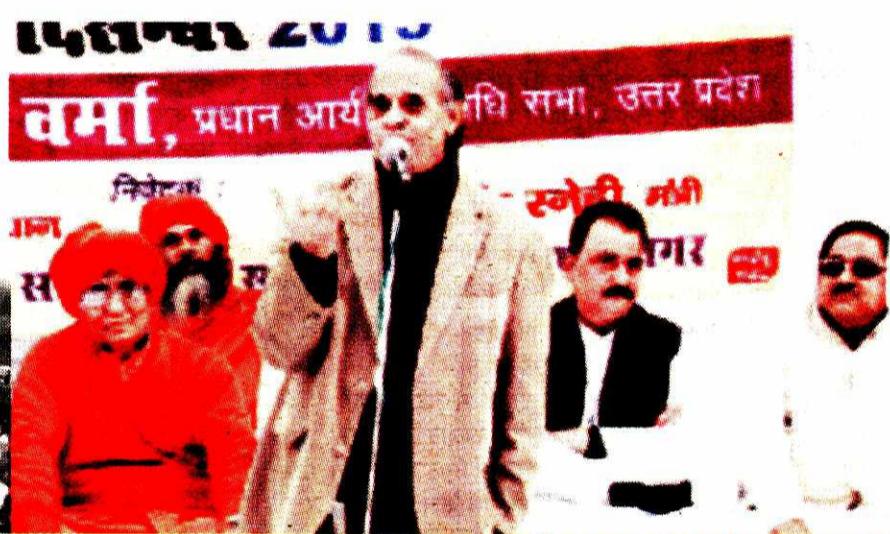
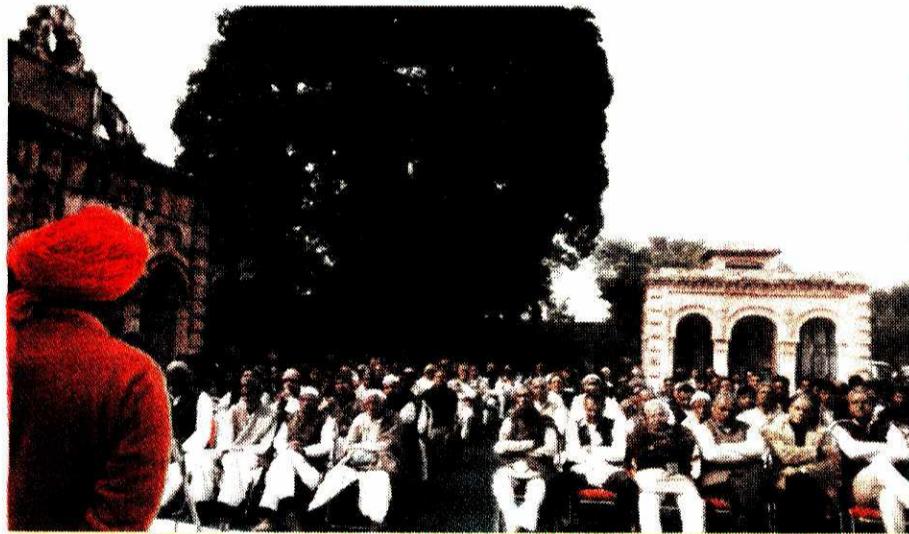
शुल्क :- एक प्रति 5 रुपया (भारत में) वार्षिक 250 रुपये तथा आजीवन 2500 रुपये

वर्ष 9 अंक 51 26 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी, 2014 दयानन्दाब्द 190 सृष्टि सम्वत् 1960853114 सम्वत् 2070 पौ. कृ.-08

पं. रामप्रसाद बिस्मिल और अशफ़ाक उल्ला खाँ के बलिदान से प्रेरणा लेकर समाज में सद्भाव पैदा करें

— स्वामी अग्निवेश

यज्ञ में आहुति दिलवाकर स्वामी अग्निवेश जी ने दिलवाया मुजफ्फरनगर के आमजनों को संकल्प



मुजफ्फरनगर में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए स्वामी अग्निवेश जी तथा ओजस्वी कवि श्री हरिओम पंवार कविता पाठ करते हुए मंच पर आसीन स्वामी अग्निवेश जी, स्वामी वेदात्मवेश और श्री देवेन्द्र पाल वर्मा जी

आर्य समाज मार्ग आर्य समाज मुजफ्फरनगर में 19 दिसम्बर को महान क्रान्तिकारी पं. राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफ़ाक उल्ला खाँ के बलिदान दिवस “सांझी शहादत, सांझी विरासत” कार्यक्रम का भव्य आयोजन कर मनाया गया। इस अवसर पर विशेष यज्ञ में आहुति देकर क्रान्तिकारियों के बलिदान से प्रेरणा लेकर आम जनता को समाज में सद्भाव पैदा करने का संकल्प दिलवाया गया।

इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध समाज सेवी तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी अग्निवेश जी, प्रसिद्ध कवि श्री हरिओम पंवार, सर्वधर्म संसद के संयोजक तथा स्वामी अग्निवेश जी के वरिष्ठ सहयोगी श्री मनुसिंह, आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के प्रधान श्री देवेन्द्र पाल वर्मा, श्री शांति प्रकाश शास्त्री, श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्री विजय गुप्ता, ठाकुर ओम पाल आर्य, श्री राजेश्वर आर्य, श्री तजिम प्रधान, श्री राजपाल आर्य, श्री अब्बास, श्री

विजय सिंह तथा श्री नौशाद जी सहित सैकड़ों गणमान्य हिन्दू-मुस्लिम व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर क्रान्तिदर्शी संन्यासी स्वामी अग्निवेश जी ने भारत के बलिदानी इतिहास के पन्ने पलटते हुए पं. राम प्रसाद बिस्मिल और अशफ़ाक उल्ला खाँ की मित्रता की मिसाल देते हुए कहा कि पं. राम प्रसाद बिस्मिल और अशफ़ाक उल्ला खाँ भारत माँ की आजादी के परवानों की कतार में एक ऐसी बेमिसाल जोड़ी थी जिसे याद करके आज भी आँखों में आसू छलछला जाते हैं। भारत माता को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपनी जिन्दगी और

जबानी हस्ते-हस्ते कुर्बान कर दी थी और आज उसी देश में वोटों की राजनीति और अवसरवाद ने हम सबको धर्म और मत के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया है। आज देश में कुछ चन्द लोग साम्प्रदायिकता का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, एक वर्ग के लोग अपने को देश भक्ति का ठेकेदार बताकर अन्य वर्गों की देशभक्ति को शक की नजरों से देख रहे हैं और इसके विपरीत आजादी से कुछ समय पूर्व एक कट्टर आर्य समाजी राम प्रसाद बिस्मिल और एक मुस्लिम नौजवान अशफ़ाक उल्ला खाँ एक साथ ही गुलामी की वेदियाँ तोड़ने का सपना देखते थे और एक ही थाली में खाना खाते थे। दोनों में सगे भाइयों जैसा प्यार था। स्वामी जी ने कहा कि अमर शहीदों की इस विरासत को हम इतनी जल्दी कुछ व्यक्तियों के पागलपन के कारण बरबाद कर

देंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास ही न कर सकें कि आजादी की बुनियाद में हिन्दू-मुसलमान दोनों की कुर्बानी शामिल थी। स्वामी जी ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए बिस्मिल और खान की मैत्री और देश भक्ति और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। देश में और खासकर इस क्षेत्र में विषैली ताकतें हम सबको धर्म और मत के आधार पर विभाजित करने का प्रयास कर रही हैं हमें ऐसी शक्तियों से सावधान रहना है। संकीर्णता को त्यागकर हम सबको देश की उन्नति के लिए कार्य करना है।

इससे पूर्व विशेष यज्ञ के अवसर पर स्वामी अग्निवेश जी ने उपस्थित समुदाय को यज्ञ में आहुति देकर संकल्प दिलवाया कि क्रान्तिकारियों के बलिदान से प्रेरणा लेकर वह समाज में सद्भाव पैदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से जिले में बढ़ रही दो समुदायों के बीच की खाई को ढूर करने का संकल्प ले।

इस अवसर पर वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्री हरिओम पंवार ने अपने शब्दों में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपनी कविताओं से माहौल को देश भक्ति से सराबोर कर दिया। उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री देवेन्द्र पाल वर्मा, कस्तूर सिंह स्नेही, करन सिंह स्नेही आदि ने भी शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अल्पतः सफल रहा।

साम्प्रदायिक सद्भाव यात्रा में तिथि परिवर्तन

अब 27 जनवरी से 30 जनवरी, 2014 तक

पहली जनवरी 2014 को प्रस्तावित एक घंटे की मानव श्रृंखला (हरिद्वार से मुजफ्फरनगर होकर दिल्ली राजघाट तक) अब मौसम आदि की प्रतिकूलता के मद्देनजर एक विशाल सभा के रूप में 27 जनवरी को मुजफ्फरनगर से आरम्भ होकर शामली, बड़ौत, मेरठ, गाजियाबाद होकर दिल्ली राजघाट और किसानघाट पर समाप्त होगी। यह सुझाव 19 दिसम्बर को आर्य समाज मुजफ्फरनगर में एकत्रित आर्य समाज तथा हिन्दू मुस्लिम समाज के नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया।

इस यात्रा की तैयारी के लिए व्यापक जन-संपर्क की तैयारी के लिए स्वामी अग्निवेश जी, सरदार वी. एम. सिंह तथा राष्ट्रीय कवि श्री हरिओम पंवार, श्री मनुसिंह, श्री देवेन्द्र पाल वर्मा, पं. माया प्रकाश त्यागी, मोहम्मद मूसा कासमी, श्री प्रभात पंत, श्री मंजीत सिंह कोचर आदि क्षेत्र का दौरा करेंगे और लगभग 20-25 वाहनों के काफिलों के साथ जगह-जगह विशाल जन-सभाओं को संबोधित करते हुए साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों के घावों में मरहम लगाने, आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत का पैगाम देने और पुराने विश्वास के रिश्तों को फिर बहाल करने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर से दिल्ली आयेंगे। भाग लेने के इच्छुक साथी सम्पर्क करें:-

- मनु सिंह, दूरभाष : -011-23363221, e-mail : agnivesh70@gmail.com

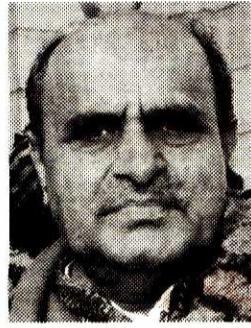
111वें जन्म दिवस पर विशेष

चौधरी चरण सिंह की याद में

आज स्वतंत्रता संग्राम के नायक और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का 111वाँ जन्मदिन है। इसे किसान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज हिन्दुस्तान के लगभग 180 जिले और सात राज्य नक्सलबाद की लपटों में झुलस रहे हैं। देश के किसानों के क्या हाल है, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने करीब 80 साल पहले जो कदम उठाए थे, अगर उन पर ध्यान दिया गया होता तो आज ये गंभीर समस्यायें पैदा ही नहीं होतीं। पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह के जन्मदिन पर उनका स्मरण कर रही हैं राजनीति की दो शख्सियत.....

वे ग्रामीण भारत का गौरव थे

- के. सी. त्यागी



आज चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है यानी आज हम किसान दिवस मना रहे हैं, लेकिन ग्रामीण भारत की क्या हालत है, किसान किन विषम परिस्थितियों में है, यह किसी से छिपा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2.94 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आज किसानों को उसके उत्पादक का लागत मूल्य मिलना भी मुश्किल हो गया है। तीन दशकों में यह पहली बार हुआ है, जब चीनी मिल मालिकों ने गन्ना उत्पादकों को घोषित समर्थन मूल्य देने से इनकार कर दिया। राज्य और केन्द्र सरकार किसानों को मदद करने के बजाय चीनी मिल मालिकों के लिए प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने में लगी हैं। यूपीएससी समेत शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में मात्रभाषा में परीक्षा देने पर रोक लग रही है। लिहाजा, ग्रामीण भारत के छात्रों की प्रशासनिक सेवाओं में साझेदारी लगातार घट रही है। सामाजिक बराबरी के सिद्धान्त का स्थान जातीय वैमनस्य एवं प्रतिस्पर्धा ले चुकी है।

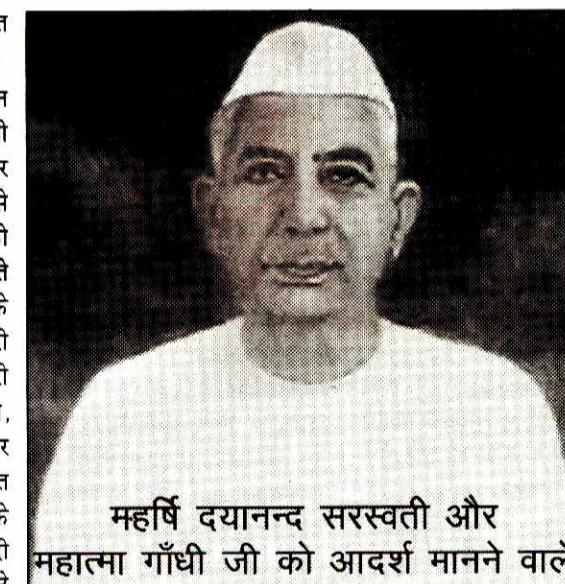
आरक्षण और विशेष अवसर का सिद्धान्त राजनीतिक सौदेबाजी का औजार बन गया है। देश में सामंती व्यवस्था के कारण और अधूरे भूमि सुधारों एवं नई उदारवादी नीतियों के चलते देश के लगभग 150 जिलों में आपात स्थित जैसे हालात हैं। सरकारें भूमि सुधार के बजाय इसे कानून व्यवस्था का प्रश्न बनाकर और उलझाने में लगी हैं। चौधरी चरण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन काल में उपरोक्त प्रश्नों का ही उत्तर तलाशने का प्रयास किया। उनके राजनीतिक उत्तर-चढ़ाव के घटनाक्रमों पर भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन गांधी और दयानन्द के सच्चे अनुयायी और ग्रामीण भारत के सभी जाति समूहों एवं वर्गों के कल्याणकारी कार्यों पर कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं है। इस लेख के जरिये उनके द्वारा शुरू किये गये ग्रामीण भारत की आजादी के स्वप्न को साकार करने के संकल्प को दोहराना है।

महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कानून तोड़ने का आहवान करके स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ को नई अग्नि प्रदान की थी, उसी समय लगभग 28 वर्ष की अल्पायु में इस लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे चौधरी चरण सिंह अपनी दीर्घकालीन सोच से आजादी के बाद उभरने वाली विषम परिस्थितियों में उत्तरे भारत को उभरने में लगे थे। वह अपनी दूरदर्शी से आने वाले कल को पढ़ते हुए उन मुद्दों पर बात कर रहे थे, जो उस समय की कांग्रेस पार्टी के लिए एजेंडे से बाहर या अप्रासारिक थी। भारतीय राजनीति में चौधरी चरण सिंह के दो अति विशिष्ट योगदान रहे। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार का जो क्रांतिकारी काम उन्होंने किया, उससे गरीब किसानों, पिछड़ों और दलितों के आर्थिक और सामाजिक हालात में गुणात्मक परिवर्तन आया। उन्होंने उत्तरी भारत की पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना पैदा की और उन्हें सत्ता के नए शक्ति केन्द्र के रूप में उभारा। इसके परिणाम स्वरूप हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कांग्रेस के विपक्ष को सबल आधार मिला और छठे दशक के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें अस्तित्व में आई।

आज जहां हिन्दुस्तान के लगभग 180 जिले और सात राज्य नक्सलबाद की लपटों में झुलस रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद केन्द्र एवं राज्य सरकारें इससे पार पाने में विफल हैं, लेकिन इस बारे में चौधरी चरण सिंह ने करीब 80 साल पहले जो कदम उठाए थे, अगर इन पर ध्यान दिया गया होता तो आज ये गंभीर समस्यायें उत्पन्न नहीं होतीं। उन्होंने नारा दिया था, 'देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है'। चौधरी चरण सिंह ने जितने कार्य किए, उनमें प्राथमिकता वाले कार्य जो गरीबों के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं, उनमें सर्वप्रथम है - उन्होंने 1928 में किसानों के मुकदमों के फैसले करवाकर उनको आपस में लड़ने के बजाय आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने का साकार प्रयास किया। वर्ष 1939 में ही ऋण विमोचक विधेयक पास करवाकर किसानों के खेतों की 'नीलामी बचाई' और सरकारी ऋणों से मुक्ति दिलाई चौधरी चरण सिंह ने 1939 में ही किसानों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 60 फीसद एवं दलितों और वर्चितों के लिए भी 20 फीसद आरक्षण दिलाने का प्रस्ताव रखा था। यह बात और है कि यथास्थितवादी कांग्रेसियों के विरोध के कारण इसमें सफलता नहीं मिल पाई। बता दें कि उस समय ग्रामीण जनसंख्या लगभग 80 फीसद थी। अगर उस समय इस प्रस्ताव को मान लिया जाता तो शायद आज हमारे देश का समाज इतना विभाजित नहीं होता और अमीरों और गरीबों के बीच की दूरी इतनी न बढ़ी होती और न ही शहरों की आबादी पर इतना बोझ पड़ता, न ही नक्सलबाद जैसी गंभीर समस्या खड़ी होती।

वर्ष 1939 में चौधरी चरण सिंह ने किसानों को इजाफा लगान व बेदखली के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए 'भूमि उपयोग बिल' का मसौदा तैयार करवाया और 1952 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास करवाकर एक प्रशंसनीय कार्य किया। हालांकि चौधरी चरण सिंह सरकारी नौकरियों में किसानों के लिए 60 फीसद, आरक्षण की लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन किसानों के हित के लिए उनकी लड़ाई उनके पूरे राजनीतिक जीवन की प्राथमिकता रही।

(लेखक राज्य सभा संसद हैं)



महर्षि दयानन्द सरस्वती और
महात्मा गांधी जी को आदर्श मानने वाले
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह

आज भी प्रासंगिक हैं उनके विचार

- शिवपाल सिंह यादव



चौधरी चरण सिंह का नाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अग्रणी है, जिन्होंने आजादी के बाद भी भारत के नवानीर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोकतंत्र को व्यापक आधार दिया। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। अच्छे विद्यार्थी होने के बावजूद उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान और स्वाभाविक मेधा का प्रयोग घर-परिवार चलाने के बजाय देश की बेहतरी में लगाया। एक राजनेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसान नेता, प्रधानमंत्री और आपातकाल के योद्धा के रूप में पूरा देश उनके योगदान से अवगत है, लेकिन बतौर अर्थशास्त्री व समाज सुधारक चौधरी साहब ने जो कार्य किए, उस पर कभी व्यापक चर्चा नहीं हुई।

23 दिसम्बर यानी आज ही के दिन चौधरी मीर सिंह व नेत्र कौर के उत्तर के रूप में 1902 में जन्मे चरण सिंह प्रारम्भ से ही पदाई-लिखाई में तेज और देश-प्रेम की भावना से ओत प्रोत थे। उनकी अंग्रेजी की जानकारी से प्रभावित होकर प्रख्यात विद्वान जे जे थामसन ने उन्हें अंग्रेजी में परास्नातक करने की सलाह दी, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने गांधीवादी दृष्टिकोण के कारण अर्थशास्त्र व इतिहास को चुना। उन्होंने हिन्दी के लिए वकालत पेशे में काफी नुकसान उठाया। भारत छोड़ो आन्दोलन (1942) के दौरान उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, बल्कि डॉ. लोहिया व लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तरह भूमिगत होकर आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ परचे आदि प्रकाशित करवाकर जनमत बनाते रहे।

ब्रिटिश हुकूमत ने चौधरी साहब पर ढाई हजार का इनाम रखते हुए बागी व फरार घोषित कर दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें देखते ही गोली मारने का भी आदेश जारी हो चुका था।

वे बाद में गिरफ्तार जरूर हुए, लेकिन तब तक अपना काम कर चुके थे। वे पाली बार 1937 में बागात गजियाबाद क्षेत्र से विधानसभा पहुँचे थे। उन्हें लेकर एक बड़ी भ्रांति फैलाई गई कि चौधरी साहब घोर जातिवादी थे, जबकि ऐसा कदापि नहीं था। विद्यार्थी जीवन में एक जाटव (दलित) के साथ भोजन करने के कारण अपनी बिरादरी में बहिष्कार का दंश झेलने वाले चौधरी साहब को बड़ौत स्थित जाट हाईस्कूल के प्रबंधन ने 1932 में अपने यहां उप-प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया। उस समय चौधरी साहब का पूरा परिवार वित्तीय संकट में था। भारी पारिश्रमिक व सुख-सुधाराओं वाले प्रस्ताव को चौधरी साहब ने महज इसलिए दुकरा दिया कि कॉलेज के पहले 'जाट' शब्द लगा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश का नेता विरोधी दल राजेन्द्र सिंह जी की जगह 'नेताजी' मुलायम सिंह यादव को यह कहते हुए बनाया कि 'मुलायम सिंह ही मेरा उत्तराधिकारी हैं, जो गरीबों, वर्चितों और किसानों की बात करता है, उनके लिए लड़ता है। मुलायम ही मेरे नाम व कार्यक्रमों को आगे बढ़ायेगा।'

चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के राजस्व, सिंचाई, कृषि जैसे विभागों के मंत्री, दो बार मुख्यमंत्री और देश के गृहमंत्री, उप-प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री तक रहे, लेकिन उनका कद इन पदों में ऊँचा रहा। वे लगभग तीन दशक तक भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश की सियासत व लोकजीवन के केन्द्र में रहे। देश में भू-सुधारों, चक्रबंदी और जमींदारी उन्मूलन के लिए उन्हें हमेशा याद किया जायेगा। उन्होंने लाखों पकड़ जमीन की सीलिंग कराकर भूमिहीन किसानों में बांटा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। आपातकाल के दौरान उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ गिरफ्तार क

समाज शिक्षा के लिए कोडला बाबूराम की आवश्यकता

जनता ने लम्हों लड़ाई के बाद सन् 2002 थे देश के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार, 86वें संविधान संशोधन के साथ सम्पूर्ण हो सका, परन्तु यह अधिकार अपने आप में अपूर्ण तथा सारे बच्चों को शिक्षा के दायरे में शामिल किए बगैर था। देश भर से विरोध के स्वर उभरे कि इस अपूर्ण अधिकार को दुरुस्त किया जाए तथा 0-6 वर्ष के छूट गए लागभग 17 करोड़ बच्चों को भी संवैधानिक दायरे में शामिल किया जाए, ताकि देश स्कूली शिक्षा शुरू करने के लिए अपने बच्चों को तैयार करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। पर हाल में संसद द्वारा पारित 'शिक्षा के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009' ने भी इस गलती को सुधारने का कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया। साथ ही 14-18 साल तक के बच्चे भी मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिये गये। संवैधानिक अधिकारों की दूसरी बड़ी खामी यह थी कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की मर्जी पर डाल दिया गया। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1993 में जे. पी. उनीकृष्णन बनाम अन्ध प्रदेश सरकार के मुकदमे में दिए गए फैसले का उल्लेख जरूरी है, जिसमें 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी तय कर दी गई थी और उसके बाद भी बच्चे की शिक्षा जारी रखी जायेगी, जो राज्य की आर्थिक क्षमता व विकास पर निर्भर करेगी। इस फैसले और तत्पश्चात् नागरिक समूहों की सक्रियता ने ही सरकार को संवैधानिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद-21 (अब 21-अ) में संशोधन करने के लिए मजबूर कर दिया था। पर यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सामने कमजोर साबित हुआ। अब जबकि शिक्षा का संवैधानिक अधिकार तथा उसको लागू करने का शिक्षा अधिनियम-2009 पारित हो गया है और इसे 1 अप्रैल, 2010 से देश भर में लागू घोषित कर दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि यह कानून देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ख़रा नहीं उत्तरता है। इसमें ढर

स्कूल मैनेजमेंट कमिटी यदि जीवन्त ढंग से गठित हों और ठीक से कार्य कर पायें तो स्कूलों में सुधार लाने के साथ ही इसे समान शिक्षा के लिए एक देशव्यापी मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कानून में निगरानी की व्यवस्था बहुत कमजोर है जो केन्द्र व राज्य के बाल संरक्षण आयोग की सक्रियता पर बहुत कुछ निर्भर है। इसीलिए इस कानून के सकारात्मक पहलुओं को लागू करा पाने का बहुत कुछ दारोमदार जनता के संगठनों पर ही निर्भर है। देश में एक मजबूत लॉबी है जो सरकारी स्कूलों को भी निजी हाथों में सौंपने का अभियान चलाती रहती है ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद सरकारी स्कूलों के ढाँचों पर कब्जा जमाया जा सके और स्कूली शिक्षा से भी ढेर सारा मुनाफा बटोरा जा सके। यह ध्यान रखना होगा कि कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए जरूरी है कि सरकारी स्कूल न केवल सरकारी क्षेत्र में बचे रहें, बल्कि ठीक से उनकी गुणवत्ता उन्नति करती रहे। सरकारी नीतियों के दोहरेपन पर भी रोक लगाना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप और विशेष प्रतिभा विद्यालयों, मॉडल स्कूल, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालयों आदि को सरकारी क्षेत्रों में खोलने तथा उन्हें आम सरकारी स्कूलों के मुकाबले ज्यादा धन व सुविधाएँ आवंटित करने की नीतियों पर भी सवाल उठाना होगा। आप ही सोचिए यदि सरकारी संरक्षा में विशेष सुविधा के साथ केन्द्रीय विद्यालय आदि की गुणवत्ता निजी विद्यालयों की तुलना में बेहतर बनाकर रखी जा सकती है तो जनता के लिए उपलब्ध कम बजट वाले आम सरकारी स्कूल क्यों नहीं बेहतर हो सकते हैं?

सारे ऐसे छिद्र हैं जो बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के मामले में न केवल रोड़ा हैं, बल्कि स्कूली शिक्षा के बाजारीकरण और निजीकरण के लिए नए दरवाजे खोलते हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो शिक्षा खरीद-फरोख्त की

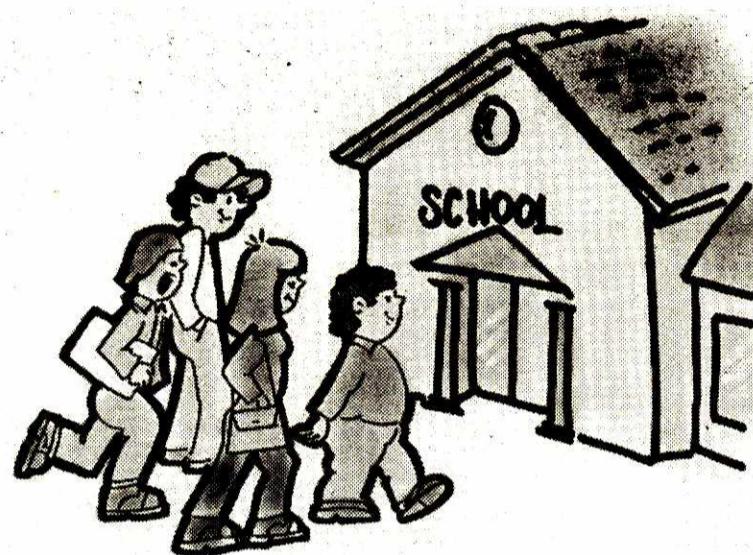
बस्तु बनी रहने वाले और शिक्षा में 'समान अवसरों को गारंटी' एक दूर की कौड़ी साबित होगी। हमारे देश में शिक्षा के मामले में 'स्कूल की उपलब्धता, गुणवत्ता और सभी के लिए समान अवसरों का होना' हमेशा से चिन्ता का विषय रहा है। देश की सामाजिक बनावट व आर्थिक श्रेणीबद्धता 'सभी के लिए एक जैसी शिक्षा' के सिद्धान्त के सामने हमेशा यक्ष प्रश्न रही है और शिक्षा हमेशा स्तरीय खांचों में बंटी रही है। वर्गीय

अध्ययन सभी विषय पढ़ते उसका बिल जाया करते हैं। इन स्कूलों में लम्हभूमि 10 साल अध्ययनकों की कमी बनी हुई है। शिक्षाविद प्रोफेसर कोठारी के शब्दों में - 'अमीरों के लिए शिक्षा और गरीबों के लिए साक्षरता' - वर्तमान में शिक्षा के मौजूदा ढाँचे की यही तार्किक परिणति है। स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च, सन् 1910 में ही भारत में 'मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा' के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद् के समक्ष प्रस्ताव रखा था जो निहित स्वार्थों के विरोध के चलते अन्ततः खारिज हो गया था। सन् 1937 में महात्मा गांधी ने सार्वभौमिक शिक्षा की बात की परन्तु विरोधियों के रुख को देखकर उन्होंने स्व-वित्त पोषित नई तालीम में समाधान खोज लिया और 'ज्ञान की दुनिया को काम की दुनिया' के साथ जोड़ने की वकालत की ताकि राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया जा सके, बाबा साहब अम्बेडकर को भी संविधान सभा में 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का संवैधानिक अधिकार दिलाने के मामले में तरह-तरह के विरोध झेलने पड़े।

अन्ततः उन्हें स्वार्थों के विरोध के चलते अन्ततः खारिज हो गया था। सन् 1937 में महात्मा गांधी ने सार्वभौमिक शिक्षा की बात की परन्तु विरोधियों के रुख को देखकर उन्होंने स्व-वित्त पोषित नई तालीम में समाधान खोज लिया और 'ज्ञान की दुनिया को काम की दुनिया' के साथ जोड़ने की वकालत की ताकि राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया जा सके, बाबा साहब अम्बेडकर को भी संविधान सभा में 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का संवैधानिक अधिकार दिलाने के मामले में तरह-तरह के विरोध झेलने पड़े।

अन्ततः उन्हें अनुच्छेद-45 को मौलिक अधिकारों की जगह नीति निर्देशक सिद्धान्तों में डालना पड़ा, जिसमें 10 वर्षों तक 0-14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुहैया करने का वायदा किया गया था। बाबा साहब ने दलितों के लिए जो तीन सूत्र दिये उसमें पहला ही शिक्षा ग्रहण करने का था, 'शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो'। आजादी के बाद भी शिक्षा पर बहस जारी रही और तमाम तरह के आयोग गठित किए गए। संसद में भी बहसें हुईं पर कोई कारगर परिवर्तन नहीं हुआ।

1966 में 'शिक्षा आयोग' का गठन हुआ जो कोठारी कमीशन के नाम से लोकप्रिय हुआ, जिसने स्कूली शिक्षा से लेकर तकनीकी शिक्षा तक पर अपनी संस्तुतियाँ पेश कीं। स्कूली शिक्षा पर तमाम सीमाओं के बावजूद कोठारी कमीशन द्वारा की गई संस्तुतियाँ शिक्षा में सुधार के लिए मील के पथर की तरह हैं। परन्तु दुर्भाग्य है कि बार-बार प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बावजूद सरकार ने इसे लागू करने की



की तीन-चौथाई आबादी के लिए बने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा 'शिक्षा के लोकव्यापीकरण' के अन्तर्राष्ट्रीय नारे के नाम पर जारी है। इन स्कूलों में बच्चों व अध्यापकों के अनुपात की तो बात ही निराली है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 बच्चों पर एक

जहमत नहीं उठाई। कोठारी कमीशन ने सामाजिक विभेदों को दूर करने के लिए शिक्षा के प्रयास शुरू करने की बात कही थी और सभी के लिए 'समान अवसर उपलब्ध' करने का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय एकता और शेष पृष्ठ 11 पर

बाल अधिकारों के रक्षक मदीबा

— कैलाश सत्यार्थी



आधुनिक विश्व राजनीति की सबसे बड़ी नैतिक हस्ती व मानवाधिकारों के महान पैरोकार स्व. नेल्सन मंडेला के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बौद्धिक और राजनीतिक जगत में काफी कुछ लिखा पढ़ा गया है। उनकी मृत्यु के उपरान्त और भी ज्यादा। परन्तु उनके महान जीवन-दर्शन का एक पक्ष लगभग अछूता सा बना हुआ है। वह है, बच्चों के अधिकारों के बारे में उनकी संवेदना, सरोकार और सार्थक कार्यों की पहल। मुझे जीवन में उनसे चार बार प्रत्यक्ष रूप से रुबरु होने का मौका मिला। उनमें से दो बार एक बाल अधिकार कार्यकर्ता के रूप में

बातचीत का भी सौभाग्य मिला। पहली बार जब वे 1994 में भारत आये थे तब क्षण मात्र के लिए उनके नजदीक खड़ा होना और हाथ मिलाना अद्भुत अनुभव था। असल सौभाग्य 1997 में मिला जब मैं 'बाल श्रम विरोधी विश्व यात्रा' की तैयारी में जोहन्सवर्ग में उनका आशीर्वाद और समर्थन लेने पहुंचा। 1998 में शुरू होने वाली इस यात्रा का एक चरण दक्षिण अफ्रीका से शुरू होना था जबकि दूसरे दो चरण, मनीला, फिलीपीन्स एवं 'सौ-पौलो (ब्राजील) से शुरू किये जाने थे। अफ्रीका वाला चरण हमने केपटाउन के पास रॉबिन ट्रीप पर स्थित उस जेल के बाहर से प्रारम्भ करने का विचार किया, जहां नेल्सन मंडेला ने 23 वर्ष कैद में गुजारे थे। इसी योजना को लेकर मैं एक सवेरे उनके आवास पर उनसे मिला। तब वे बाहर आराम कुर्सी पर बैठे थे। जब उन्हें बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व आन्दोलन के बारे में संक्षिप्त में अपनी रूपरेखा बतायी गई तो बहुत उत्साह से उन्होंने कहा कि यह बड़ी महत्वाकांक्षी और बहादुराना पहल है। उनके नजदीक बैठने और बातचीत करने से ही मैं असीमित उत्साह और हिम्मत से भर उठा था। इसी मुलाकात में मदीबा (प्यार से श्री मंडेला को इसी नाम से पुकारा जाता है) ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए युवाओं और बच्चों की भागीदारी के महत्व की एक घटना भी सुनायी। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक बार जब वे केपटाउन में एक गली में से गुरुर रहे थे तो वहां खेल रहे फुटपाथी बच्चों की भीड़ को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और बच्चों से बतियाने लगे। उत्साह में



मिजवाया, जो उनकी पत्नी और विश्व की जानी-मानी, मानवाधिकार नेत्री ग्राशा मिशेल ने दिया। उन्होंने अपने संदेश पत्र में लिखा कि मैं इस (बाल श्रम विरोधी विश्व यात्रा) अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका और दुनियाभर में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के बाल मजदूरी का शिकार होने के बारे में मैं बहुत चिंतित हूँ। इस तरह की यात्रा और अभियान बच्चों के बचपन को छीनने से रोकने तथा बाल अधिकारों के हनन से बचाने में बहुत बड़ी जन जागृति पैदा

स्वामी सर्वदानन्द संस्कृत महाविद्यालय, साधु आश्रम (अलीगढ़) के प्राचार्य डॉ. हरिवीर सिंह (आचार्य बुद्धदेव) की आकस्मिक हत्या के उपरान्त श्रद्धांजलि सभा सम्पन्न

सभा का संचालन आरम्भ करते हुए आचार्य प्रेमपाल शास्त्री, संरक्षक महाविद्यालय व संचालन समिति ने कहा कि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हरिवीर सिंह जो "बुद्धदेव" के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने अविवाहित रहकर अपना सम्पूर्ण जीवन गुरुकुल महाविद्यालय को समर्पण कर रखा था। इस महापुरुष की ज्ञात राक्षस महान प्रताप सिंह, रवि प्रताप, बिट्टू, बौबी (आदि) लोगों ने दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी थी।

आचार्य बुद्धदेव जी वेद और व्याकरण के प्रकाण्ड विद्वान और आर्य जगत में प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त थे। आचार्य जी ने कई ग्रन्थ लिखे और वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण शोध कार्य किये थे। दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को महाविद्यालय प्रागण में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम डॉ. धारणा याज्ञिकी, प्रधानाचार्य कन्या गुरुकुल, शिवगंज (सिरोही) राजस्थान के ब्रह्मत्व में शान्तियज्ञ सम्पन्न हुआ जिसमें यजमान श्री रामपाल शास्त्री और श्री नेत्रपाल जी विराज।

यज्ञोपरान्त श्रद्धांजलि सभा स्वामी सोम्यानन्द सरस्वती जी की अध्यक्षता में हुई जिसमें क्षेत्र के गणमान्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ दूरस्थ आर्य प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर डॉ. हरिवीर सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, जिसमें प्रमुख रूप से श्री रामविलास गुप्त, मंत्री आर्य समाज सिविल लाइन अलीगढ़, श्री विद्याधर शास्त्री गुरुकुल गंगीरी, अलीगढ़, स्वामी लक्ष्मणानन्द जी, आर्य गुरुकुल एटा, स्वामी धर्मेश्वरानन्द जी महामन्त्री, आर्य प्रतिनिधि सभा उ. प्र., स्वामी सोम्यानन्द सरस्वती, व्यवस्थापक, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली, स्वामी चेतनदेव, अधिष्ठाता, कन्या गुरुकुल भैयाचामड़ (अलीगढ़), आचार्य ब्रजेश जी, वैदिक साधना आश्रम, गोवर्धनपुर (अलीगढ़), डॉ. परित्रा विद्यालंकार, अधिष्ठात्री, कन्या गुरुकुल सामनी, डॉ. रामसलाल हिंदेवी, नालं बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, आचार्य स्वदेश जी, अधिष्ठाता, गुरुकुल विश्वविद्यालय दृष्टावत, भथूर, डॉ. विनय विद्यालंकार (अलीगढ़), आचार्य प्रेमपाल शास्त्री, अध्यक्ष पुरोहित सभा, दिल्ली, श्री देवनारायण भारद्वाज (अलीगढ़), श्री राजपाल शास्त्री (अलीगढ़), श्री ब्रद्धदेव शास्त्री कनकपुर, अलीगढ़ आदि गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

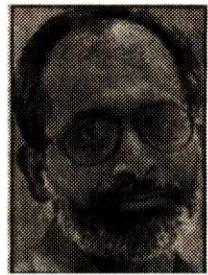
उपस्थित जन समूह ने एक स्वर से हत्यारों की भर्तसना की और डॉ. हरिवीर सिंह के कार्यों तथा उनके द्वारा भर्तवायित विश्वविद्यालय को दी गई निःस्वार्थ सेवाओं की प्रशंसा की। महाविद्यालय के शिक्षकों ने भी उनकी सेवाओं की प्रशंसा की। शान्तियज्ञ के बाद जरापान के बाद सभा विसर्जित हुई।

- आचार्य जीवन सिंह आर्य, प्राचार्य, श्री सर्वदानन्द संस्कृत महाविद्यालय साधु आश्रम, अलीगढ़

करेरी। इस तरह के निरंतर प्रयासों से ही बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति और पूरी नई पीढ़ी को इसका शिकार होने से बचाया जा सकता है। अन्ततः हमारी यह यात्रा दुनिया के 103 देशों से गुजरती हुई संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यालय जेनेवा में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई और खतरनाक या बदतर हालात के बाल श्रम को रोकने हेतु एक महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय कानून बनाने की हमारी मांग भी पूरी हुई। बाद में ग्राशा मिशेल ने हमें बताया कि इस विश्व यात्रा की सफलता पर मंडेला बहुत खुश और उत्साहित थे। दूसरी बार फिर से मुझे मदीबा के साथ मुलाकात करके एक नये आन्दोलन हेतु समर्थन व आशीर्वाद लेने का मौका मिला। 1999 में हमने विश्व शिक्षा आन्दोलन (ग्लोबल कैम्पेन फॉर एजुकेशन) की शुरूआत की थी जिसके माध्यम से दुनिया के हर छठवें व्यक्ति को अशिक्षा की प्रवरचना से मुक्ति के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय तथा आम जनता के बीच व्यापक जन आन्दोलन खड़ा किया गया। इसी सिलसिले में सन 2002 के शुरूआती दिनों में फिर से मदीबा से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस बार मुलाकात नेल्सन मंडेला फाउंडेशन में हुई जो उनके विचारों और आदर्शों को मूर्त रूप देने हेतु बनाया गया था। शिक्षा के अधिकार के आन्दोलन के हमारे प्रयासों के बारे में वे पहले से परिचित थे, क्योंकि इस मुद्रे पर हम सुश्री ग्राशा मिशेल के सम्पर्क में नियमित रूप से बने हुए थे। दोनों ने भरपूर समर्थन और प्रोत्साहन दिया। इस आन्दोलन के अन्तरराष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बात रही। मदीबा और ग्राशा ने हमें एक पत्र लिखकर कहा कि दुनियाभर के लाखों लाख अभियाक, रिक्षक और बच्चे अपनी-अपनी सरकारों से विश्व के बच्चों हेतु मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जन आन्दोलन कर रहे हैं। वे इस विश्व शिक्षा आन्दोलन के साथ हैं और हम दोनों भी उनके साथ इस आन्दोलन में अपनी आवाज शामिल कर रहे हैं। शिक्षा आन्दोलन के दौरान उनके साथ कई बार पत्राचार हुआ। एक बार उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे प्रभावशाली हथियार है। हर साल हम सौ से अधिक देशों में विश्व शिक्षा अधिकार सप्ताह मनाते हैं। इसी कार्यक्रम के सिलसिले में 2006 में हमारे अभियान से जुड़े बच्चों का एक प्रतिनिधि मंडल (हालांकि इस बार मैं स्वयं तो मदीबा से मिलने नहीं जा सका) उनसे मिला। मदीबा ने बच्चों के साथ खुब हँसी भजाक किया और उन्हें प्रेरणा दी, जो उन बच्चों के लिए जीवनभर की पूँजी बन गई। बाद में वे धीरे-धीरे अस्वस्थ रहने लगे। बाद के दिनों में मदीबा का स्वास्थ धीरे-धीरे गिरता गया परन्तु इस दौरान भी उनके परिवार के साथ हमारा सम्पर्क बना रहा। उनकी पत्नी ग्राशा मिशेल न केवल बाल अधिकारों के लिए आयोजित हमारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही हैं बल्कि हमारे द्वारा शुरू किये गए शिक्षा पर उच्च स्तरीय समूह (हाई लेवल पेनल ऑन एजुकेशन) में भी शामिल हुई। इस समूह में सुश्री ग्राशा मिशेल, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गॉर्डन ब्राउन और मैं सह अध्यक्ष हैं तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के पूर्व महासचिव श्री कोफी अन्नास, आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड, नार्वे के पूर्व प्रधानमंत्री आदि इसके सदस्य हैं। सुश्री मिशेल न केवल सक्रिय रूप से इसकी बैठकों में हिस्सा लेती हैं बल्कि अनेक महत्वपूर्ण पहल भी करती हैं। अपनी की सरकारों और राष्ट्राध्यक्षों को बाल मजदूरी की समाप्ति और शिक्षा के लिए प्रेरित करने के सुझावों के आधार पर सुश्री मिशेल ने कई महत्वपूर्ण पहलें की। 2010 में पिछले विषयक प्रयोग के दौरान दक्षिण अफ्रीका में हमने शिक्षा के अधिकार के लिए व्यापक आन्दोलन किया था। तब अरिया बार मंडला के दर्शन किये गिरनु तय वे लैलिचयर पर थे और वाला नहीं कर राकर थे। किन्तु उनका जड़ा हुआ था और यह यहां रहे। मैं वैदिक पुरुष था, जो ग्रामीण गांधीजी के स्वतंत्रता की पक्षभाव महान विजेता नेतृत्व में भड़ाला को जहां लोग नस्लवाद विरोधी थीं, जब उनके निर्माता, शान्ति एवं उदासता की मूर्ति और 21वीं शती में गांधी जी के उत्तराधिकारी के रूप में शहर रखने वाले दोह

पोर्नोग्राफी पर कैसे लठे पाबंदी

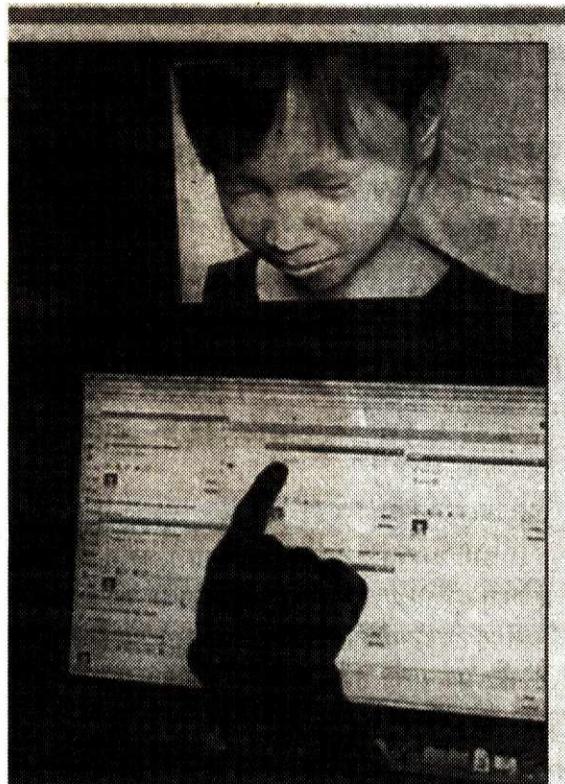
- सुभाष गाताडे



पिछले दिनों इंटरनेट के जरिये बच्चों के सैक्स टूरिज्म में शामिल हो एक सौ भारतीय पकड़े गए, जिनके नाम और फोटोग्राफ्स के साथ एक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई में चिन्हित किया गया था। इस मामले में एक संदेश देना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला एवं बाल कल्याण महकमे की तरफ से 2005 में किए गए अध्ययन में ही बताया गया है कि यहां कितने बड़े पैमाने पर बाल यौन शोषण होता है। और ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल ऐसे सौ अपराधियों को खुला छोड़ा गया तो वास्तविक जीवन में वह कितना कहर बरपा करेंगे, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होगा।

दरअसल, यह प्रसंग तब शुरू हुआ, जब बच्चों के अधिकारों के लिए सक्रिय अंतरराष्ट्रीय संस्था टेरेस डेस होम्स ने इसे लेकर एक अहम खुलासा किया। इससे पूरी दुनिया में चिंता की एक लहर दौड़ गई। अपने कम्प्यूटर की एनिमेशन तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने 10 साल की एक फिलीपिनी लड़की 'स्वीटी' को परदे पर ही 'निर्मित' किया और उसके जरिये अपने-अपने वेबकैम के माध्यम से बच्चों के सैक्स टूरिज्म में मुक्तिला एक हजार लोगों को चिन्हित किया। ये एक हजार लोग 71 अलग-अलग देशों में सम्बद्ध रखते थे, जिनमें से 254 अमेरिका से, 110 ब्रिटेन से तो 100 भारत से थे।

रिसर्च यही बताता है कि ऐसे वयस्कों को पहचानना काफी आसान होता है। अपने जिस दफ्तर में संस्था के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर हान्स गुड ने पत्रकारों से बात की थी, उसमें पीछे उन तमाम लोगों की तस्वीरें चर्चा की गई थीं, जिन्होंने स्वीटी नामक आभासी बच्ची से पैसे के बदले अपने वेबकैम के सामने तहर-तरह की अश्लील छवियाँ बनाने की बात की थी। उनके मुताबिक इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि पुलिस तब तक हरकत में नहीं आती, जब तक पीड़ित



इसे संयोग कह सकते हैं कि 'स्वीटी' प्रसंग के बाद बाल पोर्नोग्राफी उद्योग पिछले दिनों सुर्खियों में आया, जब एक के बाद एक गिरोहों का पर्दाफाश हुआ। गूगल, याहू आदि बड़ी कम्पनियों ने इस पर पाबंदी लगाने के लिए कदम बढ़ाए तो देश की आला अदालत भी इस मामले में हरकत में आई। कनाडा की पुलिस ने बाल यौन शोषण में लिप्त वैश्विक स्तर पर चल रहे गिरोह का जिस तरह पर्दाफाश किया और किस तरह कई देशों से शिक्षक, डॉक्टर और अभिनेता समेत 350 लोगों को गिरफ्तार कराया और 386 बच्चों को मुक्त कराया, वह समूचा किस्सा अपने आप में इस बात को उजागर कर रहा था कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बने तो किस तरह कदम उठ सकते हैं।

'ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज' (रूटलेज, 2012) में मिडलसेक्स विश्वविद्यालय में अपराध विज्ञान की प्रोफेसर एलेना मारेलोजो व्यापक होती जा रही इस परिघटना पर निगाह डालती हैं। ऑनलाइन बाल यौन पर्यटन किस तरह बाद में वास्तविक जीवन में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है, यह भी वह बताती है।

वैसे इसे संयोग कह सकते हैं कि 'स्वीटी' प्रसंग के बाद बाल पोर्नोग्राफी उद्योग पिछले दिनों राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया, जब एक के बाद एक गिरोहों का पर्दाफाश हुआ। गूगल, याहू आदि बड़ी कम्पनियों ने इस पर पाबंदी लगाने के लिए कदम बढ़ाए तो देश की आला अदालत भी इस मामले में हरकत में आई। कनाडा की पुलिस ने बाल यौन शोषण में लिप्त वैश्विक स्तर पर चल रहे गिरोह का जिस तरह पर्दाफाश किया और किस तरह कई देशों से शिक्षक, डॉक्टर और अभिनेता समेत 350 लोगों को गिरफ्तार कराया और 386 बच्चों को मुक्त कराया, वह समूचा किस्सा अपने आप में इस बात को उजागर कर रहा था कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बने तो किस तरह कदम उठ सकते हैं।

गौरतलब था कि इस मामले में कनाडा की पुलिस ने 2010 से जांच शुरू की थी और इस मामले में इंटरपोल के अलावा ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, मैक्सिको, नार्वे, ग्रीस सहित 50 से अधिक देशों की पुलिस के साथ काम किया। यों तो सबसे पहले इससे संबंधित मामला 2005 में उजागर हुआ था, जब 2005 में टोरंटो की पुलिस के सामने बच्चों के अश्लील वीडियो वितरण के मामले का खुलासा हुआ था।

फिर एक ही दिन के अखबार में इससे जुड़ी दो अहम खबरें प्रकाशित हुईं। पता चला कि गूगल ने बच्चों से सम्बन्धित अश्लील वीडियो यानी पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इसके जरिये एक लाख से ज्यादा सर्च में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के परिणाम नजर नहीं आयेंगे। गूगल इंजीनियरों ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर यूट्यूब के लिए वीडियो पहचानने की विकसित इस नई तकनीक का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। यों तो अभी यह योजना अंग्रेजी बोलने वाले देशों में ही लागू हुई है, मगर छह माह के अंतराल में 158 भाषाओं पर इसे लागू किया जायेगा।

इसी दिन खबर मिली की सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी कर पूछा कि देश में अश्लील वेबसाइटों खासकर बच्चों से सम्बन्धित इस तरह की वेबसाइटों पर किस तरह रोक लगाई जा सकती है। पीठ ने यह आदेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल इंदिरा जयसिंह के यह कहे जाने के बाद पारित किया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में वेबसाइटों के नियमितीकरण का मसला नहीं आता है। मालूम हो कि मंत्रालय को इस मामले से पहले भी नोटिस जारी किया गया था, मगर मंत्रालय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

अगर हम बारीकी से देखें तो यह नए प्रकार की बाल प्रताड़ना दर्जनों कानूनों के जरिये प्रतिबंधित की गई है। इसके बावजूद वह हर दिन हजारों हजार बार घटित होती है। इंटरनेट हमेशा फ्री होना चाहिए, मगर वह कानून का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। हम याद कर सकते हैं कि इस साल की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में एक बच्ची के साथ हुई यौन अत्याचारी छोड़ गये थे, गिरफ्तारियों के बाद उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्होंने पहले पोर्न क्लिप देखी थी और फिर उन्होंने अपने मकान में रहने वाली उस छोटी सी बच्ची को टाफी का लालच देकर अपने पास बुला लिया था। इसके बाद घृणित कार्य को अंजाम दिया।

- दैनिक जागरण से साभार

रिपोर्ट दर्ज न करें। लेकिन बच्चे ऐसे मामले कभी रिपोर्ट करते ही नहीं।

इसकी व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ और अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी के अध्ययन के मुताबिक किसी भी वक्त आप कम्प्यूटर पर

साढ़े सात लाख लोगों को देख सकते हैं, जो बच्चों को इस तरह अपना शिकार बना रहे हैं। मगर अभी तक ऐसे छह लोग ही दंडित हो सके हैं। कम्प्यूटर पर बच्चे से संपर्क साधना और उस पर नियंत्रण कायम कर उसे अपनी यौनकुंठा पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना। कई लोग अपने वैबकैम के सामने बच्चे के सैक्सुअल एक्ट देखकर प्रमुदित होते हैं तो कुछ अपने वश में आए बच्चे को कहीं मिलने के लिए बुलाते हैं और वहां उसे अपनी यौनकुंठा का शिकार बनाते हैं।

अगर सरकारें गम्भीर हों और बाल अधिकारों के प्रति सचेत हों, तब वह ठोस कदम उठा सकती है। अभी पिछले साल गार्डियन में खबर आई थी कि किस तरह चाइल्ड एक्स्प्लायटेशन एण्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन सेंटर की पहल पर 40 विभिन्न पुलिस बलों के अफसरों ने ब्रिटेन के तमाम ठिकानों पर छापे मारे और 76 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया, जो इंटरनेट के माध्यम से बाल यौन शोषण में मुक्तिला थे। इनमें कोई स्काउट का कर्णधार था, कोई पेंशनशुदा अध्यापक था तो कोई सेना का सदस्य। अपनी किताब 'ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज' (रूटलेज, 2012) में मिडलसेक्स विश्वविद्यालय में अपराध विज्ञान की प्रोफेसर एलेना मारेलोजो व्यापक होती जा रही इस परिघटना पर निगाह डालती हैं। ऑनलाइन बाल यौन पर्यटन किस तरह बाद में वास्तविक जीवन में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है, वह भी वह बताती है।

भ्रामक विज्ञापन और बाजार का खेल

- लक्ष्मीकांता चावला
अप्रत्यक्ष से भाजपा की पूर्व विधायिका

अपने किए कार्यों को विज्ञापित करना, उत्पादों का प्रचार करना तथा अपनी संस्थाओं के सदकार्यों को जनसाधारण तक पहुँचाने की चाह हर व्यक्ति में रहती है, इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। समय-समय पर विज्ञापनों के ढंग बदलते रहते हैं, लेकिन भाव वही रहता है। कभी ढोल बजाकर प्रचार किया जाता था, तो कभी छोटे-छोटे पत्रक बनाकर चौक चौराहों पर खड़े होकर बांटने का प्रचलन था। धीरे-धीरे यही पत्रक समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के घरों में पहुँचने लगें चौक-चौराहों में बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर भी वस्तुओं, व्यक्तियों और संस्थाओं का परिचयात्मक प्रचार किया जाता रहा है। रेडियो अर्थात् आकाशवाणी भी इस प्रचार का एक साधन बन गया था। लेकिन जैसे ही दूरदर्शन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल सामने आए तो विज्ञापन जगत पर उनका पूरा अधिकार हो गया।

वैसे भी सभी जानते हैं कि सुनने-पढ़ने से अधिक प्रभाव देखने का होता है। साहित्य जगत में भी श्रव्य काव्य से ज्यादा दृश्य काव्य की छाप गहरी होने की बात स्वीकार की गई है। अब आज के विज्ञापनों की बात की जाए तो ऐसा लगता है जैसे टीवी दर्शकों को प्रतिदिन, प्रतिपल बहुत सा झूठ निगलने को दे रहा है। क्योंकि आमजन ने मनोरंजन के लिए टेलीविजन का सहारा लिया है और अब तो टेलीविजन तथा उसके कार्यक्रम दिनचर्या का एक अपरिहार्य हिस्सा ही बन गए हैं। अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम अलग-अलग देखे जा सकते हैं, दिन में एक बार नहीं, अनेक बार हमें यह सुनना और देखना पड़ता है कि एक अभिनेता किसी ताकत की गोली हाथ में पकड़ कर दर्शकों को यह बताता है, पहले उसके पिता जी भी इसी गोली की दी हुई ताकत से जिंदा रहे और उन्हीं पिता जी के निर्देश से वह भी यह गोली खा रहे हैं।

अब प्रश्न यह है कि कौन विज्ञापन देने और प्रस्तुत करने वालों से यह पूछेगा कि यह गोली कब बनी थी, उनके पिता जी ने कब से खानी शुरू की और सच तो यह होगा कि यह गोली उन्होंने कभी खाई ही नहीं होगी। इस तरह के विज्ञापनों के एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं साथ ही लोगों को गुमराह करने का काम भी यह विज्ञापन करते हैं। जब तीन प्रमुख व्यक्तित्व तीन अलग-अलग कम्पनियों

के पानी शुद्ध करने वाले उपकरणों का प्रचार करते हैं और हरेक का यही कहना है कि जिस मशीन का पानी वह पी रहा है वही पानी इस योग्य है कि पीकर स्वस्थ रहा जाए। सवाल यह है कि कोई अभिनेता हो या खिलाड़ी, जब इन वस्तुओं का प्रचार करता है तो उन्हें तो करोड़ों रुपये मिल गए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो उन्होंने कहा वह सही ही कहा है। एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री दीवारों पर रंग-रोगन के लिए किसी उत्पादक कंपनी का प्रचार करते

हुए जब यह कहती है कि उसने अपनी घर की दीवारों पर इसी का प्रयोग किया है तो एक बार देखना अवश्य चाहिए कि उसके घर में कौन सी कंपनी का रंग-रोगन प्रयुक्त हुआ है, पर देखने की सुविधा किसी को मिलती नहीं।

इसी तरह कोई मसालों को मसाला जगत का बादशाह घोषित करता है, कोई महिला विज्ञापन में यह कहती है कि उसे पति का प्यार तब ही प्राप्त हुआ जब उसने खाने में एक विशेष प्रकार का गर्म मसाला डाल दिया। मुझे तो लगता है कि यह महिला का अपमान ही है कि उसे पति का प्यार भावना से नहीं मिलता है, बल्कि गर्म मसाले के कारण मिलता है। महिलाओं का अपमान करने वाले तो कम विज्ञापन नहीं हैं। एक युवती विज्ञापन के माध्यम से यह दिखाती है कि एक खास किस्म की क्रीम लगाने से उसकी

बिस्कुट खाओ और शेर बन जाओ, (एक खास प्रकार का पेय सचिन से भी बड़ा खिलाड़ी बना सकता है) इत्यादि, झूठे प्रचार केवल पैसे कमाने के चक्कर में टीवी चैनल कर रहे हैं। इतना ही नहीं अंधविश्वास और कुरीतियों को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के यंत्र-मंत्र जिनका न तो कोई वैज्ञानिक आधार है न ही पौराणिक उनका धंधा भी इन विज्ञापनों द्वारा ही कर दिया जाता है। ऐसा कोई साधन नहीं जिसके द्वारा न रोग मिटते हैं, न गरीबी लेकिन यह सच है कि उनकी गरीबी अवश्य मिट जाती है जिन्होंने यंत्र बेचने का काम किया। झूठ और गुमराह करने के लिए उनके विरुद्ध कहां कार्यवाही की जाए, इसके लिए भी तो कोई विभाग विशेष नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि जिस टीवी अथवा समाचार पत्रों द्वारा इन विज्ञापनों को प्रसारित किया जाता है उनके द्वारा ही उस एजेंसी का भी पता दिया जाए जहां विज्ञापन झूठे सिद्ध होने पर कार्यवाही हो।

गुमराह करने की आज्ञा भारत सरकार का सूचना व प्रसारण विभाग क्यों देता है? बिस्कुट खाओ और शेर बन जाओ, (एक खास प्रकार का पेय सचिन से भी बड़ा खिलाड़ी बना सकता है) इत्यादि, झूठे प्रचार केवल पैसे कमाने के चक्कर में टीवी चैनल कर रहे हैं। इतना ही नहीं अंधविश्वास और कुरीतियों को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के यंत्र-मंत्र जिनका न तो कोई वैज्ञानिक आधार है न ही पौराणिक उनका धंधा भी इन विज्ञापनों द्वारा ही कर दिया जाता है। ऐसा कोई साधन नहीं जिसके द्वारा उन लोगों पर कार्यवाही हो जिनके यंत्र द्वारा न रोग मिटते हैं, न गरीबी लेकिन यह सच है कि उनकी गरीबी अवश्य मिट जाती है जिन्होंने यंत्र बेचने का काम किया। झूठ और गुमराह करने के लिए उनके विरुद्ध कहां कार्यवाही की जाए, इसके लिए भी तो कोई विभाग विशेष नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि जिस टीवी अथवा समाचार पत्रों द्वारा इन विज्ञापनों को प्रसारित किया जाता है उनके द्वारा ही उस एजेंसी का भी पता दिया जाए जहां विज्ञापन झूठे सिद्ध होने पर कार्यवाही हो।

यह झूठ और गुमराह करने की कहानी बहुत लंबी है। अगर कोई सोना दिखाकर सोने की कीमत लेकर लोहा दे देता है, उसके विरुद्ध तो धोखाधड़ी का केस दर्ज हो सकता है, पर चुनावी घोषणापत्रों में सभी राजनीतिक दलों के नेता बड़े-बड़े सञ्जबाग दिखाते हैं, देश को भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात कहते हैं, पर उनके चुनाव जीतने के बाद वे स्वयं ही जनता को भयभीत करने का काम करते हैं, साथ ही भ्रष्टाचार भी करते हैं, लेकिन जनता बेचारी देखती रहती है। और वे किताबें तथा विज्ञापनपट जहां ऐसे विज्ञापन जो दिए गए थे, कहीं रही में पड़े गायब हो जाते हैं और जनता सिसकती रह जाती है।

आज की आवश्यकता यह है कि सरकार द्वारा ऐसा कोई तंत्र अवश्य ही जनता को दिया जाए जहां विज्ञापनी झूठ का शिकार हुए लोग अपनी शिकायत करके राहत पा सकें और वैसे भी विज्ञापन देने वालों पर नियंत्रण होना ही चाहिए। दो दिन पहले यह समाचार था कि सिर पर बाल उगाने के लिए जो दवाई लगाई, उससे रहे-सहे बाल भी खत्म हो गए। ऐसा बेचारा व्यक्ति कहां जाए, कहां शिकायत करे और कहां मुआवजा पा सके। ज्यादा अच्छा यह है कि जनता ही उन विज्ञापनों को नकार दे जो केवल झूठ के पुलिंदे हैं। जागरूक, सच्ची और शिक्षित समाज से यह आशा की जाती है कि विज्ञापनी झूठ से वे स्वयं को मुक्त रखें और इसका प्रतिक्रिया भी करें।

पांचजन्य से साभार



चमड़ी नरम हो गई और इसी कारण पुरुष साथी उसे प्यार करने लगा और विज्ञापन जगत की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए तब झूठ बोला गया जब लंबे और मजबूत बालों की गारंटी देने वाली एक फर्म द्वारा विज्ञापन दे रही महिला के बालों की मजबूती दिखाने के लिए उसे लंबे बालों के साथ ट्रक खींचते हुए ही दिखा दिया। शेख चिल्ली की दुनिया में भी ऐसा सम्भव नहीं, पर जब जनता चुपचाप देख लेती है और प्रश्न भी नहीं करती तो जननाभावनाओं का दुरुपयोग अथवा सदुपयोग करके अपना माल मार्केट में बेचने वालों का दोष कुछ ज्यादा नहीं रह जाता।

कौन नहीं जानता कि आधुनिकता की अतिवादी संस्कृति में भी विवाह के समय युवक-युवती का चाहे रस्म निभाने के लिए ही सही हल्दी, दही व तेल आदि के मिश्रण (उबटन) का ही लेप किया जाता है, पर विज्ञापन जगत ने इसके स्थान पर रंग-विरंगी क्रीम दिखानी और लगानी शुरू कर दी है। यह ठीक है कि इस प्रकार की औपचार्य युक्त क्रीम का प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन कभी किसी वैवाहिक रस्म में हल्दी का स्थान यह क्रीम आज तक नहीं ले सकी। प्रश्न यह है कि समाज को इस तरह



आजादी के सातवें दशक तक दिशाहीन शिक्षा ही क्यों?

- साकेन्द्र प्रताप वर्मा

भारत का तमाम प्राचीन ज्ञान वेद, उपनिषद्, पुराण तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में छिपा है, जिसे जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान जरूरी है। हमारा दुर्भाग्य है कि मथुरा व काशी में विदेशी छात्र भले ही सिर मुँडवाकर संस्कृत का ज्ञान अर्जित करने के प्रयास में जुटे हों किन्तु भारत में ऐसी हवा फैला दी गई है कि संस्कृत तो केवल पूजापाठ की भाषा है। इस हवा को फैलाने में बड़े-बड़े लोग सम्मिलित हैं। अभी कुछ दिन पहले उ. प्र. के राज्यपाल थे टी. वी. राजेश्वरा वे कुलाधिपति के रूप में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गये। वहां उन्होंने संस्कृत के विद्वानों से संबोधन में कहा कि संस्कृत पढ़ने का अर्थ बैलगड़ी युग में जीना। इसलिए यदि प्रगति करनी है तो अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। इतना सुनते ही वहाँ उपस्थित छात्र भड़क गये और राज्यपाल पर कुर्सियाँ फेंकनी शुरू कर दी। किसी तरह राज्यपाल पुलिस की सुरक्षा में जान बचाकर भागे। भारत में यही ज्ञान सोनिया गांधी के च्छेते तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भी परोसते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा से अंग्रेजी अनिवार्य कर देनी चाहिए। अमेरिका के प्रसिद्ध इतिहासकार बिलड्यूरान्ट ने लिखा है कि *India is the mother of our race and Sanskrit is the mother of India & European languages, it is mother of us all* अमेरिका के इतिहासकार को संस्कृत भाषाओं की जननी दिखाई देती है किन्तु भारत ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। इटली, जापान, चीन, रूस, जर्मनी आदि महाशक्ति बनने वाले देशों ने अपनी मातृभाषाओं में प्रगति के सारे सोपान पार किये लेकिन भारत न जाने कौन सी मतिश्रम का शिक्षाक बन गया है कि बिना अंग्रेजी हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती।

वैसे तो अंग्रेजों के गुलाम देशों पर यूरो-अमेरिकी बुद्धि का वर्चस्व है, जो उन देशों की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करती है। इस बुद्धि पर ईसाइयत का वर्चस्व है। हमें पता है कि सन् 1492 में अमेरिका भी यूरोपीय बुद्धि का शिकार हुआ था जिसकी कुटूष्टि के कारण वहाँ की सारी विशेषतायें खो गई। यही कारण है कि आज का अमेरिका यूरोपीय बुद्धि से संचालित होता है। भले ही 1992 में अपनी विशेषतायें नष्ट करने के लिए अमेरिका के एक न्यायालय ने पांच सौ साल बाद कोलम्बस को फांसी की सजा सुनाकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आजादी के बाद लगाभग यही स्थिति हमारी भी हो गई है इसीलिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था भी उसी यूरोपीय बुद्धि से संचालित होने लगी जो ईसाइयत के कब्जे में है। विद्वान मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक को जिस भाषा में सपना आता है यदि उसी भाषा में प्रारम्भिक शिक्षा दी जाये तो वह ज्यादा प्रगति कर सकता है। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम कहा करते थे कि मैं वैज्ञानिक इसीलिए बन पाया क्योंकि मेरी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होने से मेरी नींव मजबूत थी। यही बात प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बसु के पिता भगवान चन्द्र बसु जो ब्रिटिश हुक्मसे में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे वे भी कहा करते थे कि अंग्रेजी जानने से पहले मातृभाषा में अपना धरातल मजबूत होना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद केवल अंग्रेजी पर जोर होने के कारण हम बहुआयामी शिक्षा नहीं दे सके। यहाँ तक कि रोजगार सूजक शिक्षा देने की तरफ दृष्टि ही नहीं उठाई केवल बेरोजगारों की फौज तैयार करने में जुटे हैं। भारत में जो लोग रोजगार या व्यवसाय में लगे हैं उसमें से केवल 5 प्रतिशत ही प्रशिक्षित हैं जबकि कोरिया में 95 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत लोग रोजगार या व्यवसाय में लगे हैं। यहाँ पर कभी तो यौन शिक्षा के नाम पर युवाओं में नगनता फैलाने के षड्यन्त्र रचे जाते हैं और कभी सैक्स की उम्र 16 वर्ष करने पर जोर दिया जाता है। कभी विकृत इतिहास पढ़ा कर क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताने की कोशिश होती है, कभी आर्य बाहर से आये यह भ्रम फैलाया जाता है। अर्थात् भारत में सभी बाह्य आक्रांत हैं फिर चाहे मुगल हों, अंग्रेज हों या फिर यहाँ के राजे रजवाड़े। चन्द्रगुप्त, चाणक्य, पृथ्वीराज, राणप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई ही नहीं रामायण, महाभारत तक को भुलाकर भारत की गौरवशाली परम्पराओं के प्रति अविश्वास और उपहास का भाव निर्माण करने की कोशिश की जाती है। वेदों को गढ़रियों के गीत के रूप में बताया जाता है। जिससे भारत भूल जाये और इंडिया याद रहे। अर्थात् 1947 के पहले हम क्या थे यह विस्मृत हो जाये। आजादी के बाद शिक्षा व्यवसाय बन गई। चाहे जैसी फीस लो, पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ। मिड-डे-मिल, छात्रवृत्ति, लैपटाप, ड्रेस बांट दो। अच्छी मेरीट दिलवा दो लेकिन कोई प्रेरक दिशा मत दो। इसी दुरावस्था के चलते प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 7.6 प्रतिशत ही काम हो रहा है। इतनी गंभीरता पूर्वक स्वतंत्रता के बाद हमने शिक्षा के क्षेत्र को दुर्गति में पहुँचाया है?

अगर हम आजादी प्राप्त होने वाले वर्षों से तुलना करें तो 1949 में चीन में 205 विश्वविद्यालय थे, जबकि आज 2000 विश्वविद्यालय हैं। भारत में 1947 में 26 विश्वविद्यालय थे आज 538 हैं जिनमें से 153 में बुनियादी सुविधायें ही नहीं हैं। 26478 अन्य

उच्च शिक्षा संस्थान हैं जिनमें से 9875 में बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय आई. आई. एम., आई. आई. टी. तथा एम्स जैसी 100 संस्थायें हैं। अनेक निजी संस्थान तथा डीम्ड विश्वविद्यालय हैं जिनके कोई मानक ही नहीं हैं। इसी के चलते गतवर्ष 2012 में तकनीकी कॉलेजों में लगभग 2.5 लाख सीटों पर कोई प्रवेश लेने के लिए ही तैयार नहीं था। जबकि दूसरी ओर भारत से बड़ी मात्रा में छात्र-छात्रायें यूरोपियन देशों, अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रतिवर्ष जाते हैं। यह केवल छात्रों के जाने भर का मामला नहीं है इससे खरबों रुपये की विदेशी मुद्रा फीस के रूप में दुनिया के देशों को चली जाती है और हमारी अर्थव्यवस्था मुँह ताकती रहती है। हमारी प्रतिभायें पलायन करके दुनिया के देशों के काम आ रही हैं। लेकिन हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में इन बातों की कोई चिंता नहीं की। 60 करोड़ के युवा भारत में हम प्रतिवर्ष पौने दो करोड़ से ज्यादा छात्रों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते। भारत के संसद सदस्यों की प्राक्कलन समिति तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने उच्च शिक्षा के हालात पर चिंता जताई है। दुर्भाग्यवश क्यू एस. वर्ल्ड रैकिंग (यूनिवर्सिटीज) में विश्व के 200 विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत का एक भी नहीं है। एशिया के शीर्षस्थ 200 विश्वविद्यालयों में 100 तो चीन और दक्षिण कोरिया के ही हैं। इसमें भी सम्मिलित संस्था के आधार पर भारत पांचवें स्थान पर है। जब दुनिया का हर छठवाँ आदमी हिन्दुस्तान में रहता है तो भी हमारी शिक्षा की दुरावस्था देश को किस दिशा में धकेल रही है? आजादी का सातवां दशक इस सबाल के उत्तर जरूर चाहता है। भारत की प्राथमिक शिक्षा के हालात भी कम चिंताजनक नहीं हैं। थोड़े दिन

पहले सन् 2012 में गैर सरकारी संगठन 'प्रथम' ने अपनी ऐनुअल स्टेट्स इज्यूकेशनल रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। पहली कक्षा के 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कोई भाषा नहीं जानते। 57 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, जबकि जोर अंग्रेजी पर ही दिया जा रहा है। पांचवीं कक्षा के 58.3 प्रतिशत छात्र दूसरी कक्षा की पुस्तक नहीं पढ़ सकते। पांचवीं कक्षा के 46.5 प्रतिशत बच्चों को घटाना तथा 75.2 प्रतिशत बच्चों को भाग नहीं आता। इस संगठन की गुणवत्ता परीक्षा में सरकारी स्कूल के 47 प्रतिशत तथा निजी स्कूलों को 40 प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण पाये गये। माध्यमिक शिक्षा में ज्ञान का मापन केवल ग्रेडिंग तक सीमित करके बच्चों को ज्ञान विहीन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाये गये हैं। यही हालात उच्च माध्यमिक यानि कक्षा 12 में भी पैदा करने की कोशिश जारी है। हम भूल जाते हैं कि भारत तो वह देश था जहाँ

पर निरक्षर कबीर भी महान चिंतक थे। आज हम साक्षर तो बनाने में प्रयास कर रहे हैं किन्तु ज्ञान देने का प्रयास नगण्य है। भारतीय मनीषा के मर्मज्ञ तथा स्वदेश परस्त विद्वानों को शिक्षा की व्यवस्था और नीति निर्धारण में हमने या तो आजादी के बाद लगाया नहीं और अगर लगाया भी तो उनकी कही बातों पर अमल नहीं किया। हमने यह भी नहीं सोचा कि भारत को न समझने तथा भारत की माटी की गंध को न जानने वाले भारत के विकास के लिये युवा पीढ़ी को प्रेरक शिक्षा का मॉडल नहीं प्रस्तुत कर सकते। दुर्भाग्यवश हमने अंग्रेजियत में दूबे मतिश्रष्ट लोगों के सहारे देश में शैक्षिक दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जबकि दयानन्द, विवेकानन्द, गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा महर्षि अरविन्द द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में कही गई महत्त्वपूर्ण बातों की सदैव अनदेखी की। जिस शिक्षक वर्ग को पारसमणि माना गया, उसे सरकारों ने मजदूर मानने की गलती की। शिक्षक के संदर्भ में प्रख्यात कवि रघुवीर शरण मित्र ने लिखा है -

ऐसा सत्य सिखाना जग को, अनाचार मिट जाये।

मिटे स्वर्ग की असत् कल्पना, शाश्वत सत्य भूमि पर आये।

तुम भू के भगवान, तुम्हारे चरणों में इश्वर मिलते हैं।

तुम अंतर के माली, तुमसे फूल जिंदगी के खिलते हैं।

मैं भूलूँगा, पर तुम मुझसे, भूलों पर उदास मत होना।

तुम शिक्षक विद्वान, तुम्हारी प्रतिभा से लोहा भी सोना।

परन्तु स्वतंत्रता के बाद ऐसे प्रतिभावान, विद्वान तथा नूतन ज्ञान के सुजनकर्ता शिक्षक और शिक्षाविदों को देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी नहीं दी गई। शिक्षक को न तो हमने व्यवस्था का जनक बनने दिया और न ही नीतियों का निर्धारण। हम अपनी युवाशक्ति को लोहे से सोना बन

महात्मा गांधी, इस्लाम और आर्यसमाज

— डॉ विवेक आर्य, e-mail : drvivekarya@yahoo.com



Mahatma and Islam & Faith and Freedom: Gandhi in History के नाम से मुशीरुल हसन नामक लेखक की नई पुस्तक प्रकाशित हुई हैं जिसमें लेखक ने इस्लाम के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचार प्रकट किये हैं। इस पुस्तक के प्रकाश में आने से महात्मा गांधी

जी के आर्यसमाज से जुड़े हुए पुराने प्रसंग मस्तिष्क में पुनः स्मरण हो उठे। स्वामी श्रद्धानंद जी की कभी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने वाले महात्मा गांधी जी का स्वामी जी से कांग्रेस द्वारा दलित समाज का उद्धार, इस्लाम, शुद्धि और हिन्दू संगठन विषय को लेकर मतभेद था। महात्मा गांधी ने आर्यसमाज, स्वामी दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी श्रद्धानंद जी के विरुद्ध लेख 29 मई 1924 को हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य, उसका कारण और उसकी चिकित्सा के नाम से लिखा था। इस लेख में भारत भर में हो रहे हिन्दू-मुस्लिम दंगों का कारण आर्य समाज को बताया गया था। इस लेख का सबसे अधिक दुष्प्रभाव इस्लाम को मानने वालों की सोच पर पड़ा था क्योंकि महात्मा गांधी का समर्थन मिलने से उन्हें लगने लगा था कि जो भी नैतिक अथवा अनैतिक कार्य वे इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, वे उचित हैं एवं उनके अनैतिक कार्यों का विरोध करने वाला आर्यसमाज असत्य मार्ग पर हैं इसीलिए महात्मा गांधी भी आर्यसमाज और उनकी मान्यताओं का विरोध कर रहे हैं। सब पाठकगण शायद जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी द्वारा रंगीला रसूल के विरुद्ध लेख लिखने के बाद ही मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी तत्व महाशय राजपाल की जान के प्यासे हो गये थे जिसका परिणाम उनकी शहादत और इलमदीन की फाँसी के रूप में निकला था। महात्मा गांधी के आर्यसमाज के विरुद्ध लिखे गए लेख का प्रतिउत्तर आर्यसमाज के अनेक विद्वानों ने दिया जैसे लाला लाजपत राय, मिस्टर केलकर, मिस्टर सी.एस.रंगा अथवा, महात्मा टी.एल. वासवानी, स्वामी सत्यदेव जी, पंडित चमूपति जी आदि।

आर्य समाज की ओर से एक डेलीगेशन के रूप में पंडित आर्यमुनिजी, पंडित रामचन्द्र देहलवी जी, पंडित इन्द्र जी विद्यावाचस्पति जी स्वयं गांधी जी से उनके लेख के विषय में मिले परन्तु गांधी जी ने उत्तर देने के स्थान पर टाल मटोल कर मौन धारण कर लिया था।

कालांतर में सार्वदेशिक सभा दिल्ली के सदस्य श्री ज्ञानवंद आर्य जी ने अत्यंत रोचक पुस्तक उर्दू में इजहारे हकीकत के नाम से लिखी जिसका हिन्दी अनुवाद सत्य निर्णय के नाम से १६३३ में छापा गया था। इस पुस्तक में लेखक ने महात्मा गांधी द्वारा जो आरोप लगाये गये थे न केवल उनका यथोचित समाधान किया हैं अपितु गांधी जी की हिन्दू धर्म के विषय में जो भी मान्यता थी उनका उचित विश्लेषण किया है।

आर्यसमाज के प्रकाण्ड विद्वान पंडित धर्मदेव जी विद्यामार्तड द्वारा आर्यसमाज और महात्मा गांधी के शीर्षक से एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी जिसका पुनः प्रकाशन घूँड़मल ट्रस्ट हिंडौन सिटी राजस्थान ने हाल ही में किया है।

गांधी जी के शुद्धि विषयक विचार आर्यसमाज की विचारधारा के प्रतिकूल थे। गांधी जी एक ओर शुद्धि से हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा देना मानते थे दूसरी ओर मुसलमानों द्वारा गैर मुसलमानों की तब्लीग करने पर चुप्पी धारण कर लेते थे। 1921 के मालाबार के हिन्दू मुस्लिम दंगों के समय तो आर्यसमाज खिलाफत आन्दोलन के लिए मुसलमानों का साथ दे रहा था, फिर शुद्धि को हिन्दू मुस्लिम दंगों का कारण बताना असत्य नहीं तो और क्या था? मुल्तान में हुए भयंकर दंगों का कारण ताजिये के ऊपर बंधी डंडी का टेलीफोन की तार से उलझ कर टूट जाना था जिससे आक्रोशित होकर मुस्लिम दंगाइयों ने निरीह हिन्दू जनता पर भयंकर अत्याचार किये थे। कोहाट के दंगों का कारण एक हिन्दू लड़की को कुछ हिन्दू एक मुस्लिम की गिरफ्त से छुड़वा लाये थे जिससे चिढ़ कर मुसलमानों ने हथियार सहित हिन्दू बास्तियों पर हमला बोल दिया जिससे हिन्दू जनता को कोहाट से भाग कर अपने प्राण बचाने पड़े थे। एक प्रकार के अन्य दंगों का कारण खिलाफत आन्दोलन के बदली हुई मुस्लिम मनोवृत्ति, अंग्रेजों की फूट डालो

और राज करों की निति, हिन्दू संगठन का न होना एवं तत्कालीन कांग्रेस द्वारा नर्म प्रतिक्रिया दिया जाना था नाकि सत्यार्थ प्रकाश का 14वाँ समुल्लास, आर्यसमाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आन्दोलन, शास्त्रार्थ एवं लेखन कार्य था।

विस्तार भय से हम गांधी जी के विचारों को इस लेख में केवल शुद्धि विषय तक ही सीमित कर रहे हैं क्योंकि जहाँ एक ओर गांधी जी ने आर्यसमाज के शुद्धि भित्ति की भरपूर आलोचना की थी कालांतर में उन्हीं के सबसे बड़े सुपुत्र हीरालाल गांधी के मुसलमान बन जाने पर आर्यसमाज द्वारा ही शुद्धि द्वारा वापिस हिन्दू धर्म में दोबारा से शामिल किया गया था।

हीरालाल के धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन जाने पर महात्मा गांधी जी का वक्तव्य

(सन्दर्भ—सार्वदेशिक पत्रिका जुलाई अंक 1936)

महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र हीरालाल गांधी तारीख 28 मई को नागपुर में गुप्त रीती से मुसलमान बनाये गये हैं और नाम अब्दुल्लाह गांधी रखा गया हैं तथा 29 मई को बम्बई की जुम्मा मस्जिद में उनके मुसलमान बनने की घोषणा की गई।

कुछ दिन हुए यह खबर थी की वे ईसाई होने वाले हैं पर बाद में हीरालाल गांधी ने स्वयं ईसाई न होने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा है की वे अपने पिता महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण वे मुसलमान हो गये हैं।

महात्मा गांधी जी का वक्तव्य : बंगलौर 2 जून। अपने बड़े लड़के हीरालाल गांधी के धर्म परिवर्तन के सिलसिले में महात्मा गांधी ने मुसलमान मित्रों के नाम एक अपील प्रकाशित की है। अपील का आशय निम्न है:-

पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है की मेरे पुत्र हीरालाल के धर्म परिवर्तन की घोषणा पर जुम्मा मस्जिद में मुस्लिम जनता ने अत्यंत हर्ष प्रकट किया है। यदि उसने हृदय से और बिना किसी सांसारिक लोभ के इस्लाम धर्म को स्वीकार किया होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। क्योंकि मैं इस्लाम को अपने धर्म के समान ही सच्चा समझता हूँ किन्तु मुझे संदेह हैं की वह धर्म परिवर्तन हृदय से तथा बस्तु हैं, हर्ष की नहीं।

शराब का व्यासन : जो भी मेरे पुत्र हीरालाल से परिचित हैं वे जानते हैं की उसे शराब और व्यभिचार की लत पड़ी है। कुछ समय तक वह अपने मित्रों की सहायता पर गुजारा करता रहा। उसने कुछ पठानों से भी भारी सूद पर कर्ज लिया था। अभी कुछ दिनों की बात है की बम्बई में पठान लेनदारों के कारण उसको जीवन के लाले पड़े हुए थे। अब वह उसी शहर में सूरमा बना हुआ है। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी। वह हमेशा हीरालाल के पापों को क्षमा करती रही। उसके 3 संतान हैं, 2 लड़की और एक लड़का, जिनके लालन-पालन का भार उसने बहुत पहले ही छोड़ रखा है।

धर्म की नीलामी : कुछ सप्ताह पूर्व ही उसने हिन्दुओं के हिन्दुत्व के विरुद्ध शिकायत करके ईसाई बनने की धमकी दी थी। पत्र की भाषा से प्रतीत होता है की वह उसी धर्म में जायेगा जो सबसे ऊँची बोली बोलेगा। उस पत्र का वांछित असर हुआ। एक हिन्दू काउंसिलर के मदद से उसे नागपुर मुन्सीपालिटी में नौकरी मिल गई। इसके बाद उसने एक और वक्तव्य प्रकाशित किया और हिन्दू धर्म के प्रति पूर्ण आस्था प्रकट की।

आर्थिक लालसा : किन्तु घटना क्रम से मालूम पड़ता है की उसकी आर्थिक लालसाएँ पूरी नहीं हुई और उसको पूरा करने के लिए उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है। गत अप्रैल जब मैं नागपुर में था वह मुझे से तथा अपनी माता से मिलने आया और उसने मुझे बताया की किस प्रकार धर्मों के मिशनरी उसके पीछे पड़े हुए हैं। परमात्मा चमत्कार कर सकता है। उसने पत्थर दिलों को भी बदल दिया है और एक क्षण में पापियों को संत बना दिया है। यदि मैं देखता की नागपुर की मुलाकात में और हाल की शुक्रवार की घोषणा में हीरालाल में पश्चात्याप की भावना का उदय हुआ है और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया है, तथा उसने शराब तथा व्यभिचार छोड़ दिया है तो मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की ओर व्याप्ति है।

जीवन में कोई परिवर्तन नहीं : लेकिन पत्रों की खबरें इसकी कोई गवाही नहीं देती। उसका जीवन अब भी यथापूर्व है। यदि वास्तव में उसके जीवन में कोई परिवर्तन

मो. — 9310679090

होता तो वह मुझे अवश्य लिखता और मेरे दिल को खुश करता। मेरे सब पुत्रों को पूर्ण विचार स्वातंत्र्य हैं। उन्हें सिखाया गया है की वे सब धर्मों को इज्जत की दृष्टी से देखें। हीरालाल जानता है कि उसने मुझे यह बताया होता की इस्लाम धर्म से मेरे जीवन को शांति मिली है तो मैं उसके रास्ते में कोई बाधा न डालता। किन्तु हम में से किसी को भी, मुझे या उसके २४ वर्षीय पुत्र को जो मेरे साथ रहता हैं उसकी कोई खबर नहीं है।

मुसलमानों को इस्लाम के सम्बन्ध में मेरे विचार ज्ञात हैं। कुछ मुसलमानों ने मुझे तार दिया है की अपने लड़के की तरह मैं भी संसार के सबसे सच्चे धर्म इस्लाम को ग्रहण कर लूँ।

गांधी जी को चोट

मैं मानता हूँ की इन सब बातों से मेरे दिल को चोट पहुँचती है। मैं समझता हूँ की जो लोग हीरालाल के धर्म के जिम्मेदार हैं वे अहितयात से काम नहीं ले रहे जैसा की ऐसी अवस्था में करना चाहिए।

इस्लाम को हानि : हीरालाल के धर्म परिवर्तन से हिन्दू धर्म को कोई क्षति नहीं हुई उसका इस्लाम प्रवेश उस धर्म की कमजोरी सिद्ध होगा। यदि उसका जीवन पहिले की भाँति ही बुरा रहा। धर्म परिवर्तन म

हया शर्म सबकी तिलांजलि दे दी हैं। मैंने सुना है की इधर अपनी आवारा गर्दा से तुम अपने महान पिता का मजाक भी उड़ाने लग गये हो। तुम जैसे अकलमंद लड़के से यह उम्मीद नहीं थी। तुम महसूस नहीं करते की अपने पिता की अपकीर्ति करते हुए तुम अपने आप ही जलील होते हो। उनके दिल में तुम्हारे लिए सिवा प्रेम के कुछ नहीं हैं। तुम्हें पता हैं की वे चरित्र की शुद्धि पर कितना जोर देते हैं, लेकिन तुमने उनकी सलाह पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने पास रखने, पालन पोषण करने और यहाँ तक की तुम्हारी सेवा करने के लिए रजामंदी प्रगट की। लेकिन तुम हमेशा कृतच्छी बने रहे। उन्हें दुनिया में और भी बहुत से काम हैं। इससे ज्यादा और तुम्हारे लिये वे क्या करें? वे अपने भाग्य को कोस लेते हैं। परमात्मा ने उन्हें असीम इच्छा शक्ति दी हैं और परमात्मा उन्हें यथेच्छ आयु दे की वे अपने मिशन को पूरा कर सकें। लेकिन मैं तो एक कमजोर बूढ़ी औरत हूँ और यह मानसिक व्यथा बर्दाशत नहीं होती। तुम्हारे पिता के पास रोजाना तुम्हारे व्यवहार की शिकायतें आ रही हैं उन्हें वह सब कड़वी घूट पीनी पड़ती हैं। लेकिन तुमने मेरे मुँह छुपाने तक को कही भी जगह नहीं छोड़ी हैं। शर्म के मारे मैं परिवितों या अपरिवितों में उठने-बैठने लायक भी नहीं रही हूँ। तुम्हारे पिता तुम्हें हमेशा क्षमा कर देते हैं, लेकिन याद रखो, परमेश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगे।

मद्रास में तुम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के मेहमान थे। परन्तु तुमने उसके आतिथ्य का नाजायज फायदा उठाया और बड़े बेहूदा व्यवहार किये। इससे तुम्हारे मेजबान को कितना कष्ट हुआ होगा? प्रतिदिन सुबह उठते ही मैं कौप जाती हूँ की पता नहीं आज के अखबार में क्या नयी खबर आयेगी? कई बार मैं सोचती हूँ की तुम कहा रहते हो? कहा सोते हो और क्या खाते हो? शायद तुम निषिद्ध भोजन भी करते हो। इन सबको सोचते हुए बेवैनी में पलकों पर रातें काट देती हूँ। कई बार मेरी इच्छा तुमको मिलने की होती हैं लेकिन मुझे नहीं सूझता की मैं तुम्हें कहा मिलूँ? तुम मेरे सबसे बड़े लड़के हो और अब पचासवें पर पहुँच रहे हो। मुझे यह भी डर लगता रहता हैं की कहीं तुम मिलने पर मेरी बैइज्जति न कर दो।

मुझे मालूम नहीं की तुमने अपने पूर्वजों के धर्म को क्यूँ छोड़ दिया हैं, लेकिन सुना हैं तुम दूसरे भोले भाले आदमियों को अपना अनुसरण करने के लिए बहकाते फिरते हो? क्या तुम्हें अपनी कमिया नहीं मालूम? तुम धर्म के विषय में जानते ही क्या हो? तुम अपनी इस मानसिक अवस्था में विवेक बुद्धि नहीं रख सकते? लोगों को इस कारण धोखा हो जाता हैं क्यूँकि तुम एक महान पिता के पुत्र हो। तुम्हें धर्म उपदेश का अधिकार ही नहीं क्यूँकि तुम तो अर्थ दास हो। जो तुम्हें पैसा देता रहे तुम उसी के रहते हो। तुम इस पैसे से शराब पीते हो और फिर प्लेटफार्म पर चढ़कर लेक्चर फटकारते हो। तुम अपने को और अपनी आत्मा को तबाह कर रहे हो। भविष्य में यदि तुम्हारी यही करतूत रही तो तुम्हें कोई कौदियों के भाव भी नहीं पूछेगा। इससे मैं तुम्हें सलाह देती हूँ की जरा डरो, विचार करो और अपनी बेवकूफी से बाज आओ। मुझे तुम्हारा धर्म परिवर्तन बिलकुल पसंद नहीं हैं। लेकिन जब मैंने पत्रों में पढ़ा कि तुम अपना सुधार करना चाहते हो तो मेरा अन्तःकरण इस बात से अलाहादित हो गया की अब तुम ठीक जिंदगी बसर करोगे, लेकिन तुमने तो उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभी बम्बई में तुम्हारे कुछ पुराने मित्रों और शुभ चाहने वालों ने तुम्हें पहले से भी बदतर हालत में देखा हैं। तुम्हें यह भी मालूम है की तुम्हारी इन कारस्तानियों से तुम्हारे पुत्र को कितना कष्ट पहुँच रहा है। तुम्हारी लड़किया और तुम्हारा दामाद सभी इस दुःख भार के सहने में असमर्थ हो रहे हैं, जो तुम्हारी करतूतों से उन्हें होता हैं।

जिन मुसलमानों ने हीरालाल के मुसलमान बनने और उसकी बाद की हरकतों में रुचि दिखाई हैं, उनको संबोधन करते हुए श्रीमती कस्तूरबा गाँधी लिखती हैं—

आप लोगों के व्यवहार को मैं समझ नहीं सकी। मुझे तो सिर्फ उन लोगों से कहना हैं, जो इन दिनों मेरे पुत्र की वर्तमान गतिविधियों में तत्परता दिखा रहे हैं। मैं जानती हूँ की मुझे इससे प्रसन्नता भी हैं की हमारे चिर परिचित मुसलमान मित्रों और विचारशील मुसलमानों ने इस आकर्षित धटना की निंदा की है। आज मुझे उच्च मना डॉ अंसारी की उपस्थित का अभाव बहुत खल रहा है, वे यदि होते तो आप लोगों और मेरे पुत्र को सत्यरामर्श देते, मगर उनके समान ही और प्रभावशाली तथा उदार मुसलमान हैं। यद्यपि उनसे मैं सुपरिचित नहीं हूँ, जोकि मुझे आशा हैं,

तुमको उचित सलाह देंगे। मेरे लड़के को सुधारने की अपेक्षा मैं देखती हूँ कि इस नाम मात्र के धर्म परिवर्तन से उसकी आदतें बद से बदतर हो गई हैं। आपको चाहिए की

वैदिक साविदेशिक

आप उसको उसकी बुरी आदतों के लिए डांटे और उसको उलटे रास्ते से अलग करें। परन्तु मुझे यह बताया गया है की आप उसे उसी उलटे मार्ग पर चलने के लिए बढ़ावा देते हैं। कुछ लोगों ने मेरे लड़के को 'मौलवी' तक कहना शुरू कर दिया है। क्या यह उचित है? क्या आपका धर्म एक शराबी को मौलवी कहने का समर्थन करता है? मद्रास में उसके असद आचरण के बाद भी स्टेशन पर कुछ मुस्लिम उसको विदाई देने आये। मुझे नहीं मालूम उसको इस प्रकार का बढ़ावा देने में आप क्या खुशी महसूस करते हैं। यदि वास्तव में आप उसे अपना भाई मानते हैं, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेगे, जैसा की कर रहे हैं, वह उसके लिए फायदेमंद नहीं है। पर यदि आप केवल हमारी फजीहत करना चाहते हैं तो मुझे आप लोगों को कुछ भी नहीं कहना है। आप जितनी भी बुरे करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक दुखिया और बूढ़ी माता की कमजोर आवाज शायद आप में से कुछ एक की अन्तरात्मा को जगा दे। मेरा यह फर्ज हैं की मैं वह बात आप से भी कह दूँ जो मैं अपने पुत्र से कहती रहती हूँ। वह यह हैं की परमात्मा की नजर में तुम कोई भला काम नहीं कर रहे हो।

(कस्तूरबा बा के हीरालाल गाँधी के नाम लिखे गये पत्र को पड़कर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस हीरालाल के मुसलमान बनने की तीव्र आलोचना की हैं एवं समझदार मुसलमानों से हीरालाल को समझाने की सलाह दी हैं)

हीरालाल गाँधी को इस्लाम से धोखा और आर्यसमाज द्वारा उनकी शुद्धि : अब्दुल्लाह बनने के लिए हीरालाल गाँधी को बड़े बड़े सप्तने दिखाए गये थे। गाँधी जी ने तो लिखा ही था की जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा हीरालाल उसी का धर्म ग्रहण कर लेगा। हीरालाल के अब्दुल्लाह बनने के समाचार को बड़े जोर शोर से मुरिलम समाज द्वारा प्रचारित किया गया। ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा मोर्चा उनके हाथ आ गया हो। हीरालाल को आसानी से रुपया मिलने के कारण उसकी हालत बद से बदतर हो गई। उनको मुसलमान बनाने के पीछे यह उद्देश्य कदापि नहीं था की उनके जीवन में सुधार आये, उनकी गलत आदतों पर अंकुश लग सके परन्तु गाँधी जी को नीचा दिखाना था, हिन्दू समाज को नीचा दिखाना था उन्हें इस्लाम ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना था। अपने नये अवतार में हीरालाल ने अनेक स्थानों का दौरा किया एवं अपनी तकरीरों में इस्लाम और पाकिस्तान की वकालत की। उस समय हीरालाल कानपुर में थे। उन्होंने एक सभा में भाषण देते हुए कहा अब मैं हीरालाल नहीं बल्कि अब्दुल्ला हूँ। मैं शराब छोड़ सकता हूँ लेकिन इसी शर्त पर कि बापू और बा दोनों इस्लाम कबूल कर लें।

आर्यसमाज द्वारा कस्तूरबा गाँधी की अपील पर हीरालाल को समझाने के कुछ प्रयास आरम्भ में हुए पर नये नये अब्दुल्लाह बने हीरालाल ने किसी की नहीं सुनी। पर कहते हैं की झूट के पाँव नहीं होते, जो विचार सत्य पर आधारित न हो, जिस विचार के पीछे अनुचित उद्देश्य शामिल हो वह विचार सुदृढ़ एवं प्रभावशाली नहीं होता। ऐसा ही कुछ हीरालाल के साथ हुआ। हीरालाल की रातें या तो नशे में व्यतीत होती अथवा नशा उत्तरने के बाद उनकी आँखों के सामने उनकी बुढ़ी मौँ कस्तूरबा का पत्र उन्हें याद आने लगा जिससे उनका मन व्यथित रहने लगा।

उस काल में हिन्दू-मुरिलम दंगे सामान्य बात थी। एक बार कुछ मुसलमान उन्हें एक हिन्दू मन्दिर तोड़ने के लिए ले गये और उनसे पहली चोट करने को कहा। उन्हें उकसाते हुए कहाँ गया कि या तो सोमनाथ के मंदिर पर मुहम्मद गौरी ने पहली चोट की थी अथवा आज इस मंदिर पर अब्दुल्लाह गाँधी की पहली चोट होगी। कुछ समय तक चूप रहकर, सोच विचार कर अब्दुल्लाह ने कहा की जहाँ तक इस्लाम का शिक्षाओं में ऐसा कहीं नहीं पड़ा की किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना इस्लाम का पालन करना हैं और किसी भी मंदिर को तोड़ना देश की ज्वलंत समर्थ्या का समाधान भी नहीं हैं। हीरालाल के ऐसा कहने पर उनके मुरिलम साथी उनसे नाराज होकर चले गये और उनसे किनारा करना आरंभ कर दिया।

श्रीमान जकारिया साहिब जिन्होंने हीरालाल को अब्दुल्लाह बनने के लिए अनेक वायदे किये थे की तो बात करने की भाषा ही बदल गई थी। जो मुसलमान हीरालाल को बहका कर अब्दुल्लाह बना लाये थे वे अपने मनसूबे पूरे न होते देख उन्हें ही लानते देने लगे।

आखिर उन्हें गाँधी जी का वह कथन समझ में आ गया की हीरालाल को अब्दुल्लाह बनाने से इस्लाम का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अब्दुल्लाह का मन अब वापिस

हीरालाल बनने को कर रहा था परन्तु अभी भी मन में कुछ संशय बचे थे।

इतिहास की अनोखी करवट देखिये की गाँधी जी ने आर्यसमाज के शुद्धि मिशन की जहाँ खुले आम आलोचना की थी उन्हीं गाँधी जी के पुत्र हीरालाल को आर्यसमाज की शरण में वापिस हिन्दू धर्म में प्रवेश के लिए, अपनी शुद्धि के लिए आना पड़ा था।

आर्यसमाज बम्बई के श्री विजयशंकर भट्ट द्वारा वेदों की इस्लाम पर श्रेष्ठता विषय पर दो व्याख्यान उनके मन में बचे हुए बाकी संशयों की भी निवृति हो गई। जिन हीरालाल को मुसलम

पृष्ठ-3 का शेष

समान शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम की आवश्यकता

सामाजिक न्याय के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कमीशन ने पड़ोसी स्कूल की अवधारणा पर आधारित शिक्षा के एक राष्ट्रीय ढाँचे को बनाए जाने पर जोर दिया जिसे उन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम (समान विद्यालय प्रणाली) का नाम दिया, जो पूरी तरह जनता के पैसे से (सरकारी निवेश) खड़ा किया जाना था और जिसके लिए उन्होंने सन् 1966 में ही सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था। परन्तु सरकार ने पैसे की कमी बताकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अभी तक 3-4 प्रतिशत के बीच शिक्षा सम्पूर्ण बजट झूलता रहा है, जिसमें से कभी-कभी आधे से भी कम स्कूली शिक्षा पर खर्च होता है। जबकि लगभग 40 करोड़ बच्चों का भविष्य स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ है। स्कूली शिक्षा पर सरकार का यह अनौपचारिक रुख कमजोर बुनियाद पर मजबूत इमारत बनाने जैसे दिवास्वप्न की तरह ही है।

Govt Has Much to Explain on Learner Attainments

Author: J S Rajput

Published Date: Dec 22, 2013 12:00 AM

Is India really serious about educational reforms? An overview of post 2009 would indicate widespread absence of sincerity and commitment on this count

Is India really serious about educational reforms? An overview of post 2009 would indicate widespread absence of sincerity and commitment on this count. If it weren't so, the Central universities would not have been languishing under faculty shortage; HRD minister would not have admitted to the shortage of over six lakh schools teachers (in fact, it is much larger a number); ill-equipped teacher training institutions would not have been permitted to mushroom throughout the country rather unchecked. That NCTE, the statutory body created to ensure maintenance of quality and standards in teacher education, had to be taken over by the government indicates the enormity of the rot at the source. If teachers are poorly prepared, or one could become teacher by 'purchasing' a degree or diploma without receiving any knowledge or acquiring skills, the long-term damages inflicted on the young would be incalculable.

When one finds reports on how our graduates and professionals like engineers are found deficient after obtaining degrees, one can't ignore the role of teacher training institutions. In the name of reforms, MHRD invariably comes forward with more and more 'missions'. These turn out to be just schemes of additional fund allocations that are accompanied by advisories to the states/UTs on how to spend money. Recently, the Centre announced support for the creation of 5,000 academic positions in state universities. It looks fine, but the past experience in implementing Central schemes indicates how states refuse to fill in positions sanctioned under the Five-Year Plan funds. Their argument: "Who shall fund these after the expiry of Central government support?" If one single mission, the Sarva Shiksha Abhiyan, was implemented in its letter and spirit, the impact on quality would have become visible even at the university stage by now. Our non-seriousness about educational reforms is also indicated by the fact that more than 90 per cent government schools are deficient in terms of RTE Act norms. Kapil Sibal had assured the nation on April 1, 2010 that the Act would be 'fully implemented' within three years. Three years are over, Sibal has moved to greener pastures and no one is accountable for non-implementation.

Globally, learner attainments at elementary level are given increasing importance as these sow the seeds of quality in higher education and, hence, in every sector of activity related to progress and development. At present, the learning outcomes of 15-year-olds are under international discussion based upon a survey sponsored by the Organisation for Economic Cooperation and Development. Known as Programme for International Student Assessment, the survey covered half-a-million 15-year-olds in 65 countries in its second phase. India, which fared almost at the bottom of list in the first phase, backed out from the second. Internal surveys by voluntary agencies show a regular decline in learner attainments and probably to avoid an embarrassing situation, non-participation was considered a more prudent alternative. Government of India owes an explanation to the nation on this count.

China watchers must have noted that Shanghai schools have performed best and shown improvement over the previous performance. Experts there attribute it to the "mix of traditional elements and modern elements". Parents play a great role, curricula accepts new inputs and practices. In Indian reforms, politicians like 'higher pass percentage' and school boards are too ready to oblige.

People are now convinced that the only way to improve upon government schools is to take a bold decision: all those who draw their pay and emoluments from government funds shall put their child only in government schools. That, of course, would require a courageous and visionary leadership that has the foresight to pave the path for an egalitarian society.

rajput_js@yahoo.co.in

- इंडियन एक्सप्रेस से साभार

मौजूदा कानून अपनी सीमाओं के बावजूद कुछ गिनी-चुनी उपलब्धियों के साथ हमारे सामने मौजूद है, जिसका देश के बच्चों के हित में इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। इस कानून ने सभी तरह के स्कूलों के लिए (अनुदान रहित प्राइवेट स्कूलों सहित) कैपिटेशन फीस व दाखिले के लिए स्क्रीनिंग पर पाबन्दी, स्कूलों के लिए निर्धारित मापदंड का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान आदि जैसे अच्छे कदम उठाए हैं। साथ ही अध्यापकों को एक सीमा अवधि में प्रशिक्षित किये जाने तथा 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल उपलब्ध करने का प्रावधान रखा है। अनुदान रहित प्राइवेट स्कूलों में पड़ोस के गरीबों को स्कूल की कुल संख्या का 25 प्रतिशत आरक्षण भी शायद प्राइवेट स्कूलों की संरचना को प्रभावित करने में असरकारी साबित होंगे, हालांकि यह कॉन स्कूल सिस्टम का स्थानापन नहीं हो सकता है। मौजूदा कानून में स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बनाने का प्रावधान (जिसमें 75 प्रतिशत अभिभावक व 50 प्रतिशत महिलाएँ तथा कमजोर वर्गों की उचित भागीदारी) सरकारी व अर्ध सरकारी स्कूलों को सुधारने व उनकी देख-रेख करने में जनता की सक्रिय भागीदारी का स्वागतयोग्य रास्ता खोलेगा। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी यदि जीवन्त ढंग से गठित हों और ठीक से कार्य कर पायें तो स्कूलों में सुधार लाने के साथ ही इसे समान शिक्षा के लिए एक देशव्यापी मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कानून में निगरानी की व्यवस्था बहुत कमजोर है जो केन्द्र व राज्य के बाल संरक्षण आयोग की सक्रियता पर बहुत कुछ निर्भर है। इसीलिए इस कानून के सकारात्मक पहलुओं को लागू करा पाने का बहुत कुछ दारोमदार जनता के संगठनों पर ही निर्भर है। देश में एक मजबूत लॉबी है जो सरकारी स्कूलों को भी निजी हाथों में सौंपने का अभियान चलाती रहती है ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद सरकारी स्कूलों के ढाँचों पर कब्जा जमाया जा सके और स्कूली शिक्षा से भी ढेर सारा मुनाफा बटोरा जा सके। यह ध्यान रखना होगा कि कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए जरूरी है कि सरकारी स्कूल न केवल सरकारी क्षेत्र में बचे रहें, बल्कि ठीक से उनकी गुणवत्ता उन्नति करती रहे। सरकारी नीतियों के दोहरेपन पर भी रोक लगाना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और विशेष प्रतिभा विद्यालयों, मॉडल स्कूल, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालयों आदि को सरकारी क्षेत्रों में खोलने तथा उन्हें आम सरकारी स्कूलों के मुकाबले ज्यादा धन व सुविधाएँ आवंटित करने की नीतियों पर भी सवाल उठाना होगा। आप ही सोचिए यदि सरकारी संरक्षा में विशेष सुविधा के साथ केन्द्रीय विद्यालय आदि की गुणवत्ता निजी विद्यालयों की तुलना में बेहतर बनाकर रखी जा सकती है तो जनता के लिए उपलब्ध कम बजट वाले आम सरकारी स्कूल क्यों नहीं बेहतर हो सकते हैं? बशर्ते कि उन्हें जरूरी संसाधन प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जाए।

नए सन्दर्भों में नागरिक समूहों व जन अभियानों को दो स्तर पर अपने कार्यभार को जारी रखना होगा। एक, दीर्घकालिक कार्यभार के बतौर शिक्षा के समान अवसरों के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम की लड़ाई को तेज करना। दूसरा, मौजूदा कानून के अमल के लिए लोगों को न केवल जागरूक करना बल्कि इसके प्रावधानों के अमल पर निगरानी रखना और जन दबाव बनाए रखना।

- विश्व मानव से साभार

प्रिंग चित्रा नाकरा जी 'एक्सप्रेशन इण्डिया' द्वारा सम्मानित

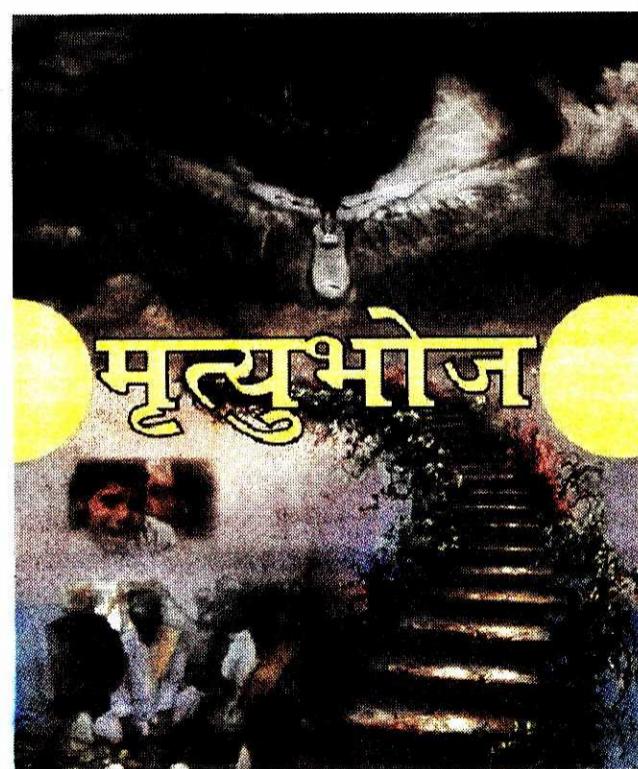


शिक्षा, समाज सेवा, कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्द्धन में विशेष योगदान प्रदान करने के कारण आर्य समाज की प्रधाना एवं वेदव्यास डी. ए. वी. पब्लिक स्कूल विकासपुरी की प्रधानाचार्या श्रीमती चित्रा नाकरा जी को 'एक्सप्रेशन इण्डिया' नामक प्रख्यात संस्था ने 'नेशनल साईंस सेन्टर नई दिल्ली' में एक भव्य समारोह में सम्मानित किया, इस अवसर पर देश के जाने माने शिक्षाविद, प्रख्यात दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाज-सेवी तथा अनेकों छात्र उपस्थित थे। प्रिंग नाकरा जी का शिक्षा में नवीन प्रयोगधर्मिता, नैतिक मूल्यों के संरक्षण, संवर्द्धन, बाल मनोविज्ञान, सेवा, स्वास्थ्य, सह-अस्तित्व कला, संस्कृति के उन्नयन, चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्माण शिविर "आध्यात्मिक चेतना सम्मेलन" तथा वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान रहा है।

'एक्सप्रेशन इण्डिया' के अध्यक्ष एवं अन्य प्रबुद्ध जनों ने प्रिंग चित्रा नाकरा जी के कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रिंग नाकरा ने कहा— "यह सम्मान आर्य समाज के दिव्य विचारों तथा गौरवशाली डी.ए.वी. संस्था के प्रेरणाप्रद संस्कारों एवं प्रोत्साहन का ही परिणाम है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने का साहस और कुछ नया कर गुजरने का हौसला देता है।" यह व्यक्तिगत रूप से मेरा नहीं वरन् समस्त आर्य समाजों एवं डी.ए.वी. संस्थाओं का सम्मान है।

"बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने रुकवाया मृत्युभोज"

मृत्युभोज आयोजन को लेकर राजस्थान के उदयपुर जिले में अफरा-तफरी मच रही है। मृत्यु के उपरान्त मृतक के परिजन मृत्युभोज का आयोजन चाहे राजी होकर करे या बेराजी उन्हें समाज के दबाव में मृत्युभोज करना अत्यन्त आवश्यक होता है।



किन्तु जब से बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने राजस्थान में मृत्युभोज उन्मूलन अधिनियम, 1960 को लागू कराने के लिए कमर कसली है तब से आयोजकों को मृत्युभोज के आयोजन में असफल होना पड़ रहा है।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा जिला-प्रशासन के साथ मिलकर 350 से भी अधिक मृत्युभोजों को रोक चुका है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के सफल होते प्रयास ने जातियों एवं धर्म के ठेकेदारों के नाक में दम कर रखा है।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यवाहक निदेशक श्री निर्मल गोराना ने उदयपुर जिले के गोगुन्दा तहसील के वजा जी का वास गांव में मृतक स्व० श्री मोहन सिंह झाला के स्वर्गवास

के उपरान्त आयोजित होने वाले मृत्युभोज को रोकने के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से उदयपुर के जिला अधिकारी, गोगुन्दा के उप-खण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं पटवारी को पत्र प्रेषित किया। जिला प्रशासन अधिकारियों ने मृत्युभोज आयोजनकर्ता मृतक के पुत्र श्री इन्द्र सिंह एवं श्री बसन्त सिंह को मौके पर पहुंचकर मृत्युभोज के आयोजन के पूर्व ही पाबन्द कर दिया और आयोजकों को मृत्युभोज करने से रोका।

उधर मृत्युभोज के निमंत्रण पर पहुंचे लोगों को भूखा तो कुछ को बीच रास्ते से ही डर के मारे वापस लौटना पड़ा। बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा मृत्युभोज के खिलाफ छेड़ी गई यह मुहीम निश्चित रूप से लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग देगी इसमें कोई दो राय नहीं हैं, साथ ही लोगों को मृत्युभोज के फिजूल खर्च से मुक्त करायेगी।

निर्मल गोराना, कार्यवाहक निदेशक – बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली

प्रो० विठ्ठलराव आर्य, सभा मंत्री, प्रकाशक व मुद्रक द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, ३/५ महर्षि दयानन्द भवन, (रामलीला मैदान/आसफ अली रोड), नई दिल्ली-110002
के लिए प्रकाशित तथा ज्योति प्रिंटिंग प्रेस, ई-१५, सैक्टर-६, नोएडा-२०१३०१ से प्रकाशित एवं मुद्रित। (फोन : ०११-२३२७४७७१, २३२६०९८५ टेलीफैक्स : २३२७४२१६)

सम्पादक : प्रो० विठ्ठलराव आर्य (सभा मंत्री) मो.:०-९८४९५६०६९१, ०-९०१३२५१५०० ई-मेल : sarvadeshik@yahoo.co.in वैबसाइट : www.vedicaryasamaj.com

प्रतिष्ठा में :-

अवितरण की दशा में लौटाएँ –
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
"दयानन्द भवन" ३/५ आसफ अली रोड, नई दिल्ली-११०००२

पाठकों के पत्र तथा प्रतिक्रिया

आपके यशस्वी सम्पादकत्व में इस विष्यात पत्र ने परिवार, समाज तथा राष्ट्र को दिव्य संस्कार, ज्ञान-विज्ञान तथा नव-चिन्तन की प्रख्यात प्रदान कर समाज एवं राष्ट्र भवित का जो सशक्त प्रमाण प्रस्तुत किया है यह हम सभी के लिए विशेष गौरव-गरिमा की बात है।

इस पत्र में प्रकाशित समस्त विषय सामग्री का स्तर इतना उच्चस्तरीय होता है कि देश के बुद्धिजीवी एवं प्रख्यात मनीषी भी उस पर खुले मन से चिन्तन एवं चर्चा करते हैं। इस उच्च स्तरीय पत्रिका के प्रकाशन के लिए सारी टीम को बधाई।

- कीर्ति बजाज, मंत्री, आर्य समाज, वेदव्यास डी.ए.वी.
पब्लिक स्कूल (सीनियर सैकेंडरी), विकासपुरी, नई दिल्ली-१८

दूरभाष:-०११-२८५३५५९४, २८५३२२९२

वैदिक सार्वदेशिक का १२ से १८ दिसम्बर का अंक अभी प्राप्त हुआ। हमेशा की तरह यह अंक भी उच्च कोटि की रचनाओं से भरपूर है तथा सामाजिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पृष्ठ २ पर स्वामी अग्निवेश जी द्वारा लिखित लेख "वैदिक समाजवाद में चिन्ताओं का समाजीकरण" वर्तमान द्वितीय व्यवस्था तथा उसके निराकरण को प्रस्तुत कर रहा है। वास्तव में आज नाकारा और स्वयं परिश्रम न करने वाले लोग दूसरे के श्रम को डकार रहे हैं तथा प्रजातान्त्रिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए अपनी संस्कृति सभ्यता और राष्ट्रीयता का मजाक उड़ाते हुए यह नौकरशाह तथा कथित राजनेता आम जनता के हक को खुले आम लूट रहे हैं। स्वामी जी का यह लेख सड़ी-गली व्यवस्था में परिवर्तन चाहने वालों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसमें दी गई व्यवस्थाओं को देश में लागू किया ही जाना चाहिए। प्रस्तुत लेख देश की गरीब पिसती जनता की असली तस्वीर दिखाने में पूर्ण रूप से सफल है। समाज सुधारकों तथा क्रांतिकारी वीरों को कुछ सबक मिल सके तो स्वामी जी का परिश्रम सफल समझा जायेगा।

-बाबूराव मितल, घाटकोपर, मुम्बई

अंधविश्वास, स्फृतिवाद, अक्तारवाद एवं पाण्डुण के खिलाफ

महर्षि दयानन्द की सिंह गर्जना

- सत्यार्थप्रकाश का

११ वां समुल्लास

मंगाये, पढ़े, पढ़वायें, बाटें, भेट करें

सहयोग राशि २० रुपये सहयोग राशि

गांधार छोड़ें शक्काहार अपनायें आस्तिर क्यों ?

लेखक - डॉ. सुरेन्द्र सिंह कादियाल

सहयोग राशि ३० रुपये

The Great Debate Between Vegetarian and Dead body eaters—

By : Manu Singh

Contribution ३० -

तीनों पुस्तकों पर

50 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ उठायें

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

"महर्षि दयानन्द भवन" ३/५ आसफ अली रोड, नई दिल्ली - ११०००२

दूरभाष :- ०११-२३२७४७७१, २३२६०९८५